नववर्ष की शुभकामनाएं

खंड १७ नंबर १ जनवरी २०२१

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

नई विश्व व्यवस्था में भारत और अर्जेंटीना

डॉ. एस. जयशंकर, भारत के माननीय विदेश मंत्री और माननीय श्री फेलिप सोला, अर्जेंटीना के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उपासना मंत्री वेबिनार को संबोधित करते हुए।

भारतीय दूतावास, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं पराग्वे और आरआईएस ने सीआईपीपीईसी के साथ मिलकर 6 नवंबर, 2020 को 'नई विश्व व्यवस्था में भारत और अर्जेंटीना' विषय पर एक आभासी (वर्चुअल) वेबिनार आयोजित किया। माननीय डॉ. एस. जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री और माननीय श्री फेलिप सोला, अर्जेंटीना के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उपासना मंत्री ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

माननीय मंत्री डॉ. जयशंकर ने अपने संबोधन में इस बात पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अर्जेंटीना के साथ हमारे संबंधों को वर्ष 2019 में एक रणनीतिक साझेदारी में परिणत कर दिया गया, जब हमारे राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए थे। पिछले दस वर्षों में हमारा द्विपक्षीय व्यापार दोगुने से भी अधिक हो गया है, और अर्जेंटीना में कई भारतीय कंपनियों की उपस्थिति तथा भारत में अर्जेंटीना की अनेक कंपनियों की मौजूदगी से हमारे मजबूत आर्थिक संबंध अब और भी अधिक प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। हालांकि, कृषि, खनन एवं खनिज, तेल व गैस, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और मोटर–वाहन (ऑटोमोटिव्स) के क्षेत्र में आपसी सहभागिता बढ़ाने के लिए पूरकता या पारस्परिक आदान–प्रदान की अब भी व्यापक गुंजाइश है। अर्जेंटीना के लोग दरअसल भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता के मुरीद हैं। अर्जेंटीना इसके साथ ही भारत की सामूहिक सांस्कृतिक

शेष पृष्ठ 13 पर जारी....

महामारी के बाद हिंद महासागर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग

आईओआरए एक बहुत बड़ा गतिशील आर्थिक समूह है। इसमें इस क्षेत्र में विकसित होने की असीम संभावनाएं हैं और यह आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जहां के वृहद बुनियादी आर्थिक तत्व विकास, महंगाई और अन्य वृहद मापदंडों की दृष्टि से अत्यंत मजबूत हैं। आईओआरए की नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) कार्यक्रम के लिए भी अत्यंत मजबूत प्रतिबद्धता है। यही नहीं, नीली अर्थव्यवस्था प्रक्रिया के साथ इसके मजबूत जुड़ाव की बदौलत इस क्षेत्र से एक मजबूत 'ब्लू वॉयस' निकल रही है जो इस क्षेत्र में नए विकास प्रतिमान की प्रासंगिकता को दर्शाती है।

इस क्षेत्र के कई देश जैसे कि मलेशिया, मॉरीशस, सेशेल्स, इत्यादि अपने यहां नीली अर्थव्यवस्था नीतियों को लागू करते हुए

शेष पृष्ठ 14 पर जारी....

माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन उद्घाटन भाषण देते हुए।

'वैश्विक स्तर पर आर्थिक बेहतरी के लिए भावी रूपरेखा: जी20 रियाद शिखर सम्मेलन और उससे परे के बारे में झलक'

तीन 'आई' (इटली, इंडोनेशिया और इंडिया) यानी इटली, इंडोनेशिया और भारत को बहुपक्षवाद की भावना में नए प्राण डालने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति फिर से तेज करने हेतु सामूहिक समाधान पेश करने के लिए दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह की मदद करने में अग्रणी भूमिका निभाने की जरूरत है। यह बात जी7 और जी20 में भारत के शेरपा माननीय श्री सुरेश प्रभु ने रेखांकित की है।

आरआईएस द्वारा सीआईआई के सहयोग से 'वैश्विक स्तर पर आर्थिक बेहतरी के लिए भावी रूपरेखा और जी20 रियाद शिखर सम्मेलन और उससे परे के बारे में झलक' विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में माननीय श्री प्रभु ने कहा कि असमानता, असहनीय ऋण बोझ, निम्न निवेश स्तर, पर्याप्त नौकरियों की कमी और पारिश्रमिक में ठहराव जैसी चिंताजनक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में कोविड–19 महामारी का प्रकोप शुरू होने से पहले से ही बहुपक्षवाद पर नए सिरे से गौर किया जा रहा था। हालांकि, इन चुनौतियों के वैश्विक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, 'बहुपक्षवाद से मुंह मोड़ना न केवल एक मूर्खता है, बल्कि

माननीय श्री सुरेश प्रभु, भारत के जी20 शेरपा

अधिक–से–अधिक आपदाओं को न्योता देने का एक निश्चित खतरा भी है।'

उन्होंने कहा कि तीन 'आई' (इटली इंडोनेशिया और इंडिया) यानी इटली, इंडोनेशिया और भारत को जी20 की अपनी–अपनी अध्यक्षता के दौरान सक्रियतापूर्वक कदम उठाते हुए ''शेष दुनिया को यह याद दिलाना चाहिए कि समाधान (इन समस्याओं का) 'आई' यानी मैं' कहने में नहीं, बल्कि हम' कहने में निहित है।'' उन्होंने कहा, ''ये तीन 'आई' भविष्य को नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं और उन्हें वैश्विक गवर्नेंस के मुद्दों पर आपस में मिलकर काम करना चाहिए। जी20 को न केवल पूरी दुनिया का मार्गदर्शन और नेतृत्व करना चाहिए, बल्कि अपने ठोस कदमों के जरिए यह भी दर्शाना चाहिए कि वही मानवता और धरती के भविष्य के लिए उत्तरदायी है।'' श्री प्रभु का कहना है कि कोविड–19 वैक्सीन को निश्चित तौर पर दुनिया भर में उपलब्ध कराने और इसके साथ ही डिजिटलीकरण और चौथी औद्योगिक क्रांति की चुनौतियों से निपटने के अलावा जी20 को जलवायु समझौते और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का प्रभावकारी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी20 को रोजगार सृजन और कौशल विकास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। संयोगवश, अमेरिका की आगामी बिडेन सरकार ने बहुपक्षवाद को अपना समर्थन देने और इसके साथ ही पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के फिर से जुड़ने का संकेत दिया है। उल्लेखनीय है कि ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर दिया था और 'जलवायु परिवर्तन में कमी पर पेरिस समझौते' से अलग कर दिया था।

ओईसीडी के जी20 शेरपा माननीय श्री निकोलस पिनाउड ने इस अवसर पर कहा कि वैसे तो आर्थिक प्रोत्साहन या स्टिमुलस पैकेजों और कोविड–19 वैक्सीन के विकसित हो जाने से उपभोक्ता और कारोबारी विश्वास काफी बढ़ गया है,

शेष पृष्ठ 19 पर जारी....

श्री निकोलस पिनाउड, ओईसीडी के जी20 शेरपा

श्री दीप कपूरिया, हाई–टेक कंपनी समूह के चेयरमैन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति पर सी. आईआई की राष्ट्रीय समिति के सह–अध्यक्ष

राजदूत मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डीजी, आरआईएस

वैश्विक व्यापार नियमन और बहुपक्षीय रूपरेखा

आरआईएस ने डब्ल्यूटीओ@25 में 'वैश्विक व्यापार नियमन और बहुपक्षीय रूपरेखाः आगे की राह' विषय पर दूसरे वेबिनार की मेजबानी की। वेबिनार श्रृंखला दरअसल आरआईएस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली आगामी विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यहां तक कि एफटीए नियम भी काफी हद तक डब्ल्यूटीओ नियमन द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, इसलिए इस वेबिनार में वैश्विक व्यापार नियमन की केंद्रीय संस्थागत संरचना के रूप में डब्ल्यूटीओ के विशेष महत्व पर चर्चा की गई। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि विश्व व्यापार संगठन में निरंतर गतिरोध जारी है और डब्ल्यूटीओ पिछले कई वर्षों में सही ढंग से कार्य नहीं

कर पाया है, पैनल ने 3 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया, ताकि विश्व व्यापार संगठन के पुनरुद्धार हेतु आगे की राह सुझाई जा सके या व्यापार बहुपक्षवाद को बचाने की प्रक्रिया के साथ देशों के विभिन्न समूहों को पुनः अधिक–से–अधिक जोड़ा जा सके।

सबसे पहले, पैनलिस्टों ने विवाद निपटान व्यवस्था (डीएसएम) में सुधार और अपीलीय निकाय में नियुक्तियां से जुड़े मतभेदों पर विचार–विमर्श किया। डब्ल्यूटीओ के अगले महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया में निहित मौजूदा बाधाओं पर भी चर्चा की गई। अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन के आसार को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही संदर्भों में अमेरिका की भूमिका का विश्लेषण किया

गया। डब्ल्यूटीओ प्रणाली के कामकाज में डीएसएम की अहम भूमिका रही है। लेकिन संबंधित व्यवस्था की रूपरेखा और इसकी कार्य प्रणाली के बारे में विगत वर्षों में प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विकसित और विकासशील दोनों ही देशों को सुधार प्रस्तावों की खासियतों को आंकना होगा। यह तथ्य अत्यंत अहम है कि अमेरिका डीएसएम में सुधारों को लागू करने की आवश्यकता के मुद्दे पर बेहद अडिग रहा है और इसने विश्व व्यापार संगठन के साथ अपने सार्थक जुड़ाव के लिए इसे एक पूर्व शर्त बताया है।

दूसरा प्रमुख फोकस क्षेत्र विकासशील देशों को दी गई विशेष एवं भिन्न (एसएंडडी) तरजीह और दोहा दौर की वार्ताओं का ठप हो जाना है जिनका व्यापक असर बहुपक्षीय वार्ताओं में एसएंडडी प्रावधानों के भविष्य पर पड़ेगा। पैनलिस्टों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत इस तरह के प्रावधानों के काफी कमजोर हो जाने पर प्रकाश डाला। कुछ विकसित देशों, विशेषकर अमेरिका के सख्त रुख से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे यह चाहते हैं कि विश्व व्यापार में व्यापक हिस्सेदारी वाले बड़े विकासशील देशों को इस तरह का लाभ पाने से वंचित कर दिया जाए। विकासशील देशों की आय और व्यापारिक क्षमताओं में भारी विविधता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि,

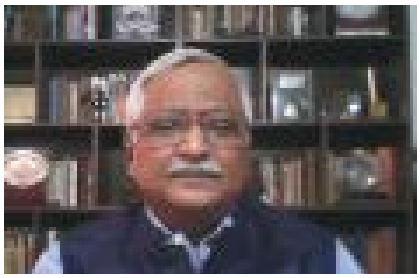

लंबे समय से जारी विकासात्मक जरूरतों और चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यह सुझाव दिया गया कि चुनिंदा विकासशील देशों के रुख में हाल में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों को अवश्य ही उन मुद्दों का विश्लेषण करना चाहिए जो उनके लिए दांव पर लगे हुए हैं और इसके साथ ही

उन्हें विश्व व्यापार संगठन में नए गठबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए।

डब्ल्यूटीओ में सुधार लाने की प्रक्रिया और विकासशील देशों के रुख या नजरिए के तहत नए मुद्दों को भी विभिन्नि मुद्दों के तीसरे सेट में शामिल किया गया। यह सुझाव दिया गया कि औद्योगिक सब्सिडी, सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों एवं डिजिटल वाणिज्य के साथ–साथ मत्स्य सब्सिडी से जुड़े प्रस्तावों के काफी दूरगामी परिणाम विकासशील देशों के लिए हो सकते हैं, और इनसे विकासशील देशों की क्षेत्रवार प्रतिस्पर्धी क्षमता की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए निपटना चाहिए। वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ एकीकरण के हिस्से के रूप में आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्वायत्तता के बारे में भी ठीक इसी तरह की विशिष्ट सोच है।

विज्ञान और नीति–निर्माण के बीच बेहतर सहयोग के लिए एक चेतावनी है कोविड –19

वैसे तो आधुनिक इतिहास में सदैव ही विज्ञान और नीति निर्माण एक–दूसरे पर निर्भर रहे हैं, यानी वैज्ञानिक अपनी ओर से नीति–निर्माताओं को सूचित करते रहे हैं और नीति–निर्माता अनुसंधान के लिए आवश्यक धनराशि मुहैया कराने एवं प्राथमिकताएं निर्धारित करने का निर्णय लेते रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी इन दोनों के बीच संबंध इतने करीब नहीं रहे हैं और इसके साथ ही इतने जटिल नहीं रहे हैं जैसा कि कोविड–19 महामारी के दौरान देखने को मिला।

वैसे तो वैज्ञानिक अवधारणाएं कोविड–19 से पहले के दौर में भी आर्थिक या सामाजिक नीतियों का निर्धारण करते समय नीति निर्माताओं द्वारा गौर की जाने वाली अलग–अलग जानकारियों में शामिल हुआ करती थीं, लेकिन अब वे ही ऐसे नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्य आधार बन गई हैं जो या तो लाखों लोगों के जीवन को बचा सकते हैं या उन्हें खतरे में डाल सकते हैं, अथवा समस्त अर्थव्यवस्थाओं को या तो तबाह कर सकते हैं या सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। चूंकि जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय क्षति जैसे वैश्विक मुद्दे, जिनके समाधान के लिए विज्ञान और नीति निर्माताओं के बीच समान रूप से गहन सहयोग की आवश्यकता होगी, अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, अतः ऐसे में यह सवाल काफी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है कि क्या कोविड–19 ने अब विज्ञान एवं नीति निर्माण के बीच नए सिरे से सहयोग करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

यूएनडीपी सियोल नीतिगत केंद्र और आरआईएस द्वारा 11 दिसंबर 2020 को संयुक्त रूप से आयोजित विशेष सत्र के दौरान कई उदाहरण पेश करते हुए यह जानकारी दी गई कि किस तरह से विभिन्न देशों और संस्थानों ने कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच ज्ञान एवं अच्छी प्रथाओं या तौर–तरीकों को आपस में साझा करने को सुविधाजनक बनाया। इसे ध्यान में रखते हुए विज्ञान और नीति के बीच प्रभावकारी सामंजस्य के लिए विभिन्न मॉडलों और संस्थागत संरचनाओं पर विचार किया जाएगा, ताकि यह दर्शाया जा सके कि किस तरह से विभिन्न देशों ने वैज्ञानिक ज्ञान या अवधारणाओं को नीतिगत निर्णयों में तब्दील कर दिया है।

इस सत्र का उद्देश्य यह पता लगाना था कि किस तरह से ज्ञान साझा करने वाले विशेषज्ञ कोविड–19 महामारी के दौरान विभिन्न नेटवर्कों को बनाने और नीति निर्माताओं एवं वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में हासिल हुए अनुभवों को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन अन्य मुद्दों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी संबंधित हितधारकों के बीच साझा किया जा सके, जिनके लिए प्रभावकारी विज्ञान–नीति सामंजस्य आवश्यक होता है। सत्र के दौरान इस विषय पर भी चर्चा की गई कि क्या देश विशेष के स्तर पर हासिल अनुभवों को आगे समेकित करने के साथ–साथ संस्थागत रूप दिया जा सकता है, ताकि वैश्विक मुद्दों से निपटने वाली बहुपक्षीय रूपरेखाओं और नजरिए में इन्हें समाहित किया जा सके।

इस दौरान प्रतिभागियों ने जिन–जिन प्रश्नों के जवाब दिए उनमें से मुख्य प्रश्न ये हैं: कोविड–19 से संबंधित मुद्दों पर विज्ञान और नीति निर्माण के बीच प्रभावकारी सहयोग को बढ़ावा देने में कौन–कौन से तरीके और संस्थागत संरचनाएं सबसे सफल साबित हुई हैं? क्या वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने के उद्देश्य से विज्ञान–नीति के सामंजस्य वाली संस्थागत संरचना को उन्नत करके बहुपक्षीय स्तर तक बढ़ाया जा सकता है; यदि हां, तो कैसे?, और ज्ञान विशेषज्ञ यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वैश्विक प्रासंगिकता वाले अन्य मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर फोकस करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य महामारी से परे भी जाकर विज्ञान–नीति में प्रभावकारी सहयोग को बनाए रखने में मददगार साबित हों।

कार्यक्रम की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के आरंभिक भाषण के साथ हुई। श्री आर्टेमी इज्मेसटीव, नीति विशेषज्ञ, यूएनडीपी सियोल नीतिगत केंद्र ने इसका संचालन किया। मुख्य वक्ता ये थेः डॉ. चेख म्बो, फ्यूचर अफ्रीका के निदेशक; डॉ. अरबिंद मित्रा, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव; डॉ. झांग चुआनहोंग, चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान के सचिव; डॉ. रथिन रॉय, प्रबंध निदेशक – अनुसंधान एवं नीति, ओडीआई; और डॉ. सानुशा नायडू, वैश्विक संवाद संस्थान में वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी। यूएनडीपी सियोल नीतिगत केंद्र के निदेशक श्री स्टीफन क्लिंगबिएल ने समापन भाषण दिया।

कोविड काल के बाद आसियान–भारत साझेदारी

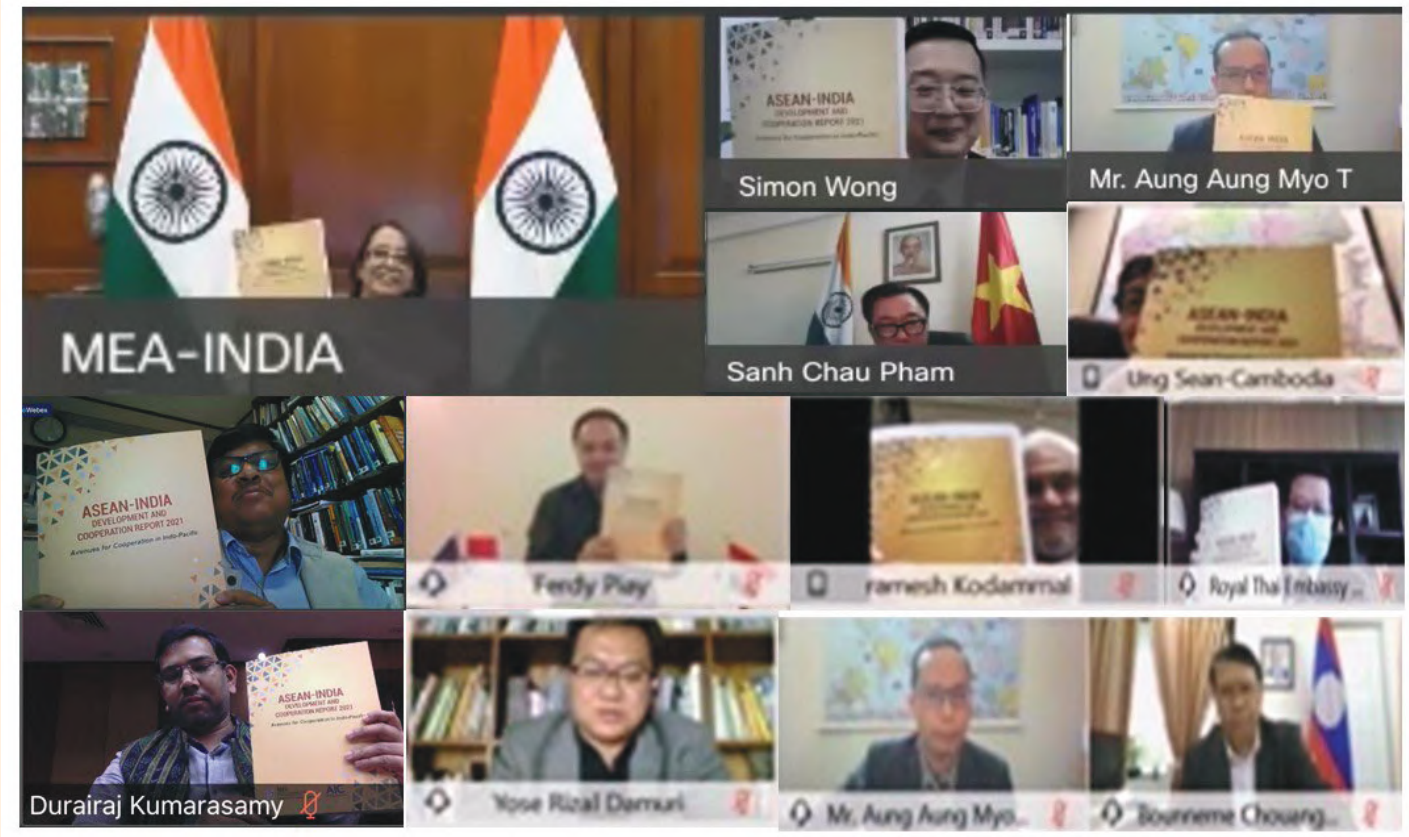

वेबिनार प्रगति पर है जिसका यह स्क्रीनशॉट है

कोविड काल के बाद 17वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2020 से पहले आसियान–भारत साझेदारी पर एक वेबिनार 10 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया और इसके साथ ही आसियान–भारत विकास एवं सहयोग रिपोर्ट (एआईडीसीआर) 2021 जारी की गई। आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने स्वागत भाषण दिया। चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने सत्र की अध्यक्षता की और विशेष भाषण दिया। श्री फर्डी निको योहानेस पियाए, मिशन के उप प्रमुख, इंडोनेशिया गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली; श्री आंग आंग मयो थीन, मिशन के उप प्रमुख, म्यांमार गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली; माननीय श्री साइमन वोंग, उच्चायुक्त, सिंगापुर गणराज्य का उच्चायोग, नई दिल्ली; और श्री फाम सान्ह चाऊ, राजदूत, वियतनाम समाजवादी गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली ने विशेष भाषण दिया।

राजदूत रिवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। इसके बाद आरआईएस स्थित एआईसी द्वारा *'आसियान–भारत विकास और सहयोग रिपोर्ट (एआईडीसीआर) 2021: हिंद–प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए अवसर'* जारी की गई।

डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस ने इस अवसर पर आयोजित पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता की। मुख्य वक्ता ये थे: डॉ. योज रिजाल दमुरी, अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख, रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (सीएसआईएस), जकार्ता; प्रो: अर्पिता मुखर्जी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर), नई दिल्ली; दातो' रमेश कोडामल, सह–अध्यक्ष, आसियान–भारत व्यवसाय परिषद (एआईबीसी), कुआलालम्पुर; और डॉ. हुयी होआंग गुयेन, निदेशक, दक्षिण–पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी (वीएएसएस), हनोई। आरआईएस स्थित एआईसी की ओर से डॉ. दुरईराज कुमारसामी ने समापन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन किया।

इब्सा में बढ़ता सहयोगः प्रमुख क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य

आरआईएस ने 10 नवंबर, 2020 को *'इब्सा में बढ़ता सहयोगः महत्वपूर्ण क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य'* नामक इब्सा रिपोर्ट का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया। अपने आरंभिक संबोधन के दौरान डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस ने इब्सा रिपोर्ट की वर्चुअल लॉन्चिंग में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मेहमानों और इब्सा फेलो का स्वागत किया। कार्यक्रम के संदर्भ का उल्लेख करते हुए आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और इब्सा के अपार योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इब्सा साझेदारी दरअसल दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) की अभिव्यक्ति है। बहुपक्षीय समाजों का उदय, लोकतंत्रों में सामंजस्य, वैश्विक विकास की संरचना के प्रति बहुपक्षवाद और संसाधनों तक सरकारों की पहुंच अत्यंत आवश्यक है। आरआईएस अपनी स्थापना के समय से ही इब्सा और इसके प्रयासों के केंद्र में रहा है। आरआईएस ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से युवा विद्वानों के अकादमिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2016 में इब्सा विजिटिंग फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। यह फेलोशिप कार्यक्रम कृषि, वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों, व्यापार और निवेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित है। इब्सा फेलो के पहले बैच (2017–2018) ने आरआईएस द्वारा प्रकाशित प्रथम रिपोर्ट में अपना अहम योगदान दिलचस्प शोध लेखों के रूप में दिया। दूसरे बैच ने भी अपने शोध लेखों का योगदान वर्तमान रिपोर्ट में दिया था, जिसे एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान के रूप में जाना जाता है। प्रो. चतुर्वेदी ने इब्सा फेलो द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी शोध पत्रों के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की और दक्षिण–दक्षिण सहयोग एवं इन देशों के थिंक–टैंकों के बीच संवाद पर संयुक्त इब्सा घोषणा पत्र जारी करने की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए एक–दूसरे से सहयोग और सीखने के लिए इब्सा के विशेष महत्व को दोहराया।

आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने लॉन्चिंग वाले सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. कुमार ने कहा कि बहुलवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा विश्वास रखने वाला इब्सा विभिन्न लोकतंत्रों के वैश्विक गठबंधन या वैश्विक शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इब्सा का संयुक्त घोषणा पत्र, जिसमें एसएससी पर विभिन्न सिद्धांतों और शर्तों को रेखांकित किया गया है, एक मार्गदर्शक चार्टर या संहिता के रूप में कार्य कर सकता है। उन्होंने विभिन्न फेलो द्वारा लिखे गए शोध लेखों में दी गई मुख्य दलीलों पर संक्षेप में चर्चा की।

श्री राहुल छाबड़ा, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से *'इब्सा में बढ़ता सहयोगः प्रमुख क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य'* नामक इब्सा रिपोर्ट का विमोचन किया। श्री छाबड़ा ने एसएससी में इब्सा के विशेष महत्व को सराहा जो सहिष्णुता, बहुसंस्कृतिवाद को मजबूत करने, सहभागी लोकतंत्र के लिए समर्पित समान विचारधारा वाले देशों का समूह है और जो सतत विकास, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने, डब्ल्यूटीओ मुद्दों, अप्रसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों, इत्यादि पर समान विचारों को साझा करता है। उन्होंने वर्तमान मुद्दों एवं चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षीय संस्थानों की सीमा को रेखांकित किया और बहुपक्षवाद एवं बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इब्सा के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला। वर्ष 2004 में अनूठा इब्सा फंड और फिर इसके बाद इब्सा फेलोशिप शुरू करना

शेष पृष्ठ 16 पर जारी....

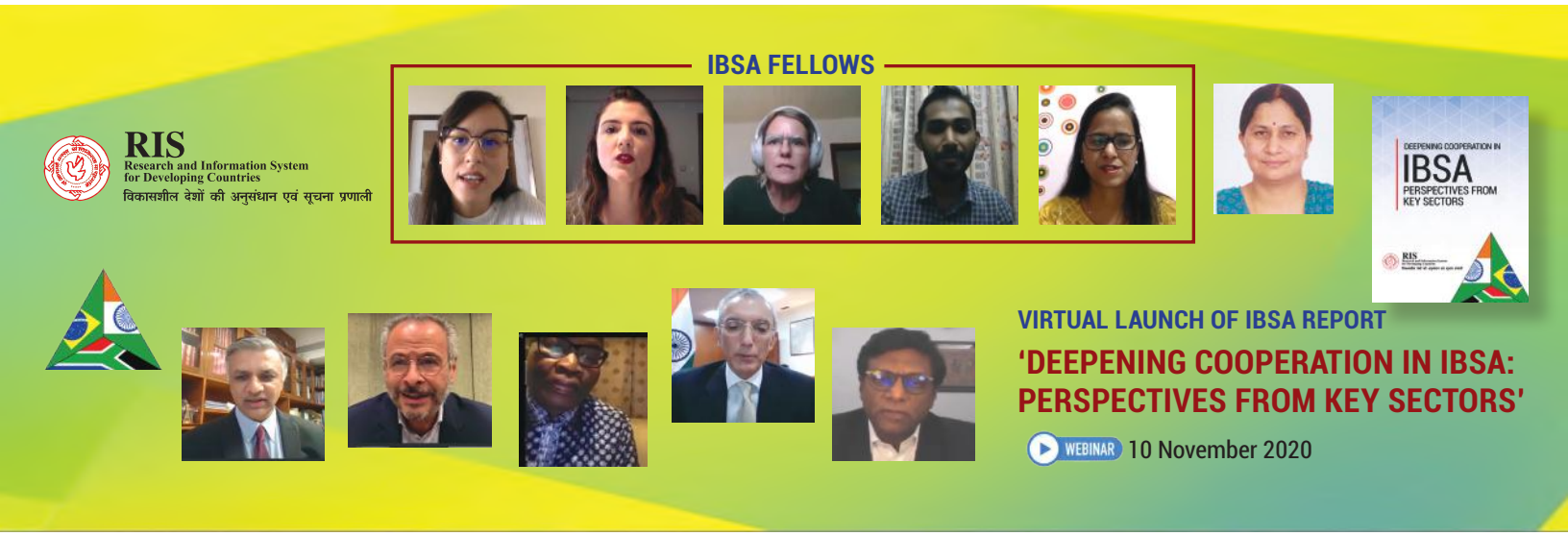

'कोविड–19 और दक्षिण एशिया में मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने के उपायः सीखने और सहयोग के अवसर'

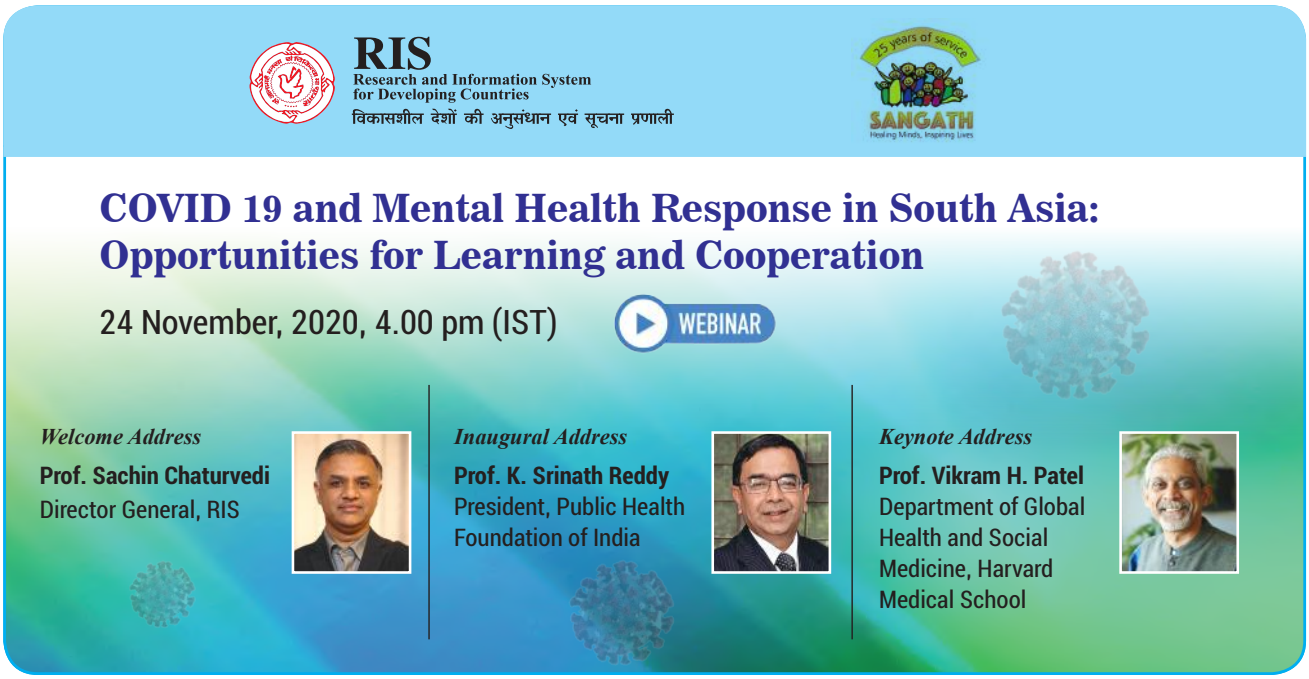

हाल के अध्ययनों में अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण एशिया की एक चौथाई से भी अधिक आबादी कम से कम एक मानसिक स्वास्थ्य विकार से निश्चित तौर पर पीड़ित है। विश्व आर्थिक फोरम का अनुमान है कि विश्व स्तर पर मानसिक बीमारियों के परिणामस्वरूप वर्ष 2010 और वर्ष 2030 के बीच 16.1 ट्रिलियन अमेरिकी डालर का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कोविड–19 ने इस स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ दिया है। इसकी मुख्य वजहें महामारी से जुड़ा भय एवं अनिश्चितता, अनजान या अपरिचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के कारण बढ़ता सामाजिक अलगाव, और वित्तीय नुकसान हैं। दक्षिण एशिया में ज्ञान और संसाधनों के आदान–प्रदान के जरिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग इन चिंताओं को दूर करने और इस बारे में सक्रिय रणनीतियां बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, इस मुद्दे को सुलझाने पर अब तक जो भी चर्चाएं की गई हैं और नीतिगत रणनीतियां अपनाई गई हैं वे बेहद अपर्याप्त रही हैं। इन मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए आरआईएस ने एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन 'संगत' के साथ मिलकर 24 नवंबर 2020 को 'कोविड–19 और दक्षिण एशिया में मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने के उपायः सीखने और सहयोग के अवसर' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। कोविड–19 के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन करने, इस क्षेत्र में अपनाई जा रही स्वास्थ्य प्रणालियों एवं तंत्रिका विज्ञान संबंधी उपायों पर चर्चा करने, और आगे की राह के बारे में योजना बनाने के लिए इस वेबिनार ने शिक्षाविदों एवं नीति निर्माताओं के साथ–साथ पूरे दक्षिण एशिया के मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान विशेषज्ञों को एकजुट किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी, अध्यक्ष, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने उद्घाटन भाषण दिया और प्रो. विक्रम पटेल, वैश्विक स्वास्थ्य और सामाजिक चिकित्सा विभाग, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने मुख्य भाषण दिया।

इसके बाद आयोजित पैनल परिचर्चा का संचालन डॉ. अनंत भान, प्रमुख, संगत, भोपाल ने किया। इसमें उपस्थित पैनलिस्ट ये थेः डॉ. सुनीमले मदुरावाला, अनुसंधान अर्थशास्त्री, नीतिगत अध्ययन संस्थान, कोलंबो; डॉ. रोहुल्ला अमीन, बिरूनी संस्थान, काबुल; प्रो. पुष्पा प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, मनोरोग विभाग, किस्ट मेडिकल कॉलेज, नेपाल; श्री मोहम्मद कमरुज्जमां, वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी, नीतिगत संवाद केंद्र, ढाका; प्रोफेसर सुरिंदर जायसवाल, उप निदेशक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई; प्रो. नीरज जैन, निदेशक, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुड़गांव; डॉ. ईश्वर वी. बसवाराडडी, निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली; और सुश्री शुभ्रता प्रकाश, निदेशक, नीति आयोग, नई दिल्ली।

'भारत में बी–20 वैश्विक संवाद' पर डिजिटल सम्मेलन

जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौते के बारे में जारी मतभेद को दूर करने की आवश्यकता है। जी–7 और जी–20 में भारत के शेरपा माननीय श्री सुरेश प्रभु ने कहा, 'दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और कारोबारी संगठनों यानी क्रमशः जी20 एवं बी20 को पेरिस जलवायु समझौते को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता देने, डिजिटल खाई को पाटने, बेहतरीन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करने, मूल्य श्रृंखलाओं एवं चिकित्सा आपूर्ति को मजबूत करने और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है।

आरआईएस द्वारा 7 अक्टूबर 2020 को सीआईआई और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सहयोग से 'भारत में बी–20 वैश्विक संवाद' विषय पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में माननीय श्री सुरेश प्रभु, जो सांसद (राज्य सभा) भी हैं, ने भारत द्वारा वर्ष 2022 में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किए जाने का जिक्र किया और कहा कि वैसे तो भारत इस दौरान अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके साथ ही वह अन्य देशों द्वारा अपनी जी20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में किए गए कार्यों को भी आगे बढ़ाएगा।

बी–20 या बिजनेस20 दरअसल जी20 देशों का कारोबारी समुदाय है और यह टी20 (थिंक टैंक), डब्ल्यू20 (महिला), सी20 (सिविल सोसायटी), वाई20 (युवा), एस20 (विज्ञान), एल20 (श्रम) और यू20 (शहरी) सहित अन्य सहभागिता समूहों के साथ मिलकर जी20 शिखर सममेलनों के लिए आवश्यक जानकारियां और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। जी20 की अध्यक्षता बारी–बारी से इसके प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक साल के लिए संभाली जाती है। वर्तमान में जी20 की अध्यक्षता सऊदी अरब संभाल रहा है जो वर्ष 2021 के लिए इसकी अध्यक्षता इटली को सौंप देगा।

वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन (शुद्ध–शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन) और वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए माननीय श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वैश्विक समस्याओं को हल करने के अपने दृष्टिकोण के तहत भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम ('दुनिया एक परिवार है)' के अपने दर्शन का पालन करेगा। यह सवाल करते हुए कि यदि कोई भी सदस्य देश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा हो, तो वैश्विक समुदाय अपने आपको समृद्ध कैसे मान सकता है, उन्होंने कारोबारी समुदाय से न केवल मुनाफा कमाने पर, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने पर भी फोकस करने को कहा। माननीय श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि कंपनियों को जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ–साथ डिजिटल खाई को पाटने में भी मदद करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते (अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया है) के बारे में जारी मतभेद को दूर करने की जरूरत है।

इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) श्री राहुल छाबड़ा ने जी20 को पेश की गई हालिया बी20 रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने के साथ–साथ उत्पादक क्षेत्रों में फिर से मजबूती बहाल करके अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशाल घरेलू मांग को पूरा करने की आवश्यकता के बावजूद भारत ने अपनी चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखा है और कई देशों को जेनेरिक दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण मुहैया कराए हैं। महामारी के मौजूदा प्रकोप के दौरान भारत ने त्वरित कार्रवाई टीमों, सूचना आदान–प्रदान प्लेटफॉर्मों और वेबिनारों के जरिए स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रशिक्षण के सहारे अन्य देशों की मदद की। इसके अलावा, भारत ने कई देशों को आवश्यक समर्थन प्रदान करके 'जी20 की ऋण अदायगी स्थगन पहल' को आगे बढ़ाया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने कहा कि यह संस्थान कारोबारियों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और सिविल सोसायटी समूहों सहित विभिन्न

शेष पृष्ठ 11 पर जारी....

डब्ल्यूटीओ@25 श्रृंखला

डब्ल्यूटीओ@25 श्रृंखला पर आरंभिक वेबिनार 22 अक्टूबर 2020 को उन परिस्थितियों में आयोजित किया गया जब महामारी के बाद वैश्विक व्यापार का परिदृश्य उत्साहजनक नहीं है और आने वाले समय में अनिश्चितताएं व्याप्त रहने को लेकर आशंकाएं हैं। उत्पादन एवं आपूर्ति में अचानक व्यवधान आ गया है और इसके साथ ही बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में व्यापक गतिरोध जारी है जो दरअसल महामारी के प्रकोप से पहले से ही बरकरार है।

वेबिनार में उत्तर और दक्षिण के अनेक टिप्पणीकार एवं बुद्धिजीवी एकजुट हुए और इस दौरान विभिन्न निहितार्थों एवं आगे की राह पर विचार–विमर्श किया गया। इस ओर ध्यान दिलाया गया कि कुछ विकासशील देश तो मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन इनका एक बड़ा वर्ग इससे वंचित रहा है और यहां तक कि विकसित देशों को हुए लाभ भी एकसमान नहीं रहे हैं। उभरती बहुध्रुवीयता के साथ–साथ विश्व शक्ति की अनचाही दिशा के कारण भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। वर्तमान परिस्थितियां दरअसल 'गैट' के दौर से बहुत भिन्न हैं, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा व्यापारिक राष्ट्र है वह एक विकासशील देश है। मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाएं प्रौद्योगिकी के मजबूत प्रभाव और संबंधित नए मुद्दों से निपटने में असमर्थ रही हैं। डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) प्रणाली को अस्तित्व के संकट से उबारने के लिए पैनल द्वारा कई सिफारिशें पेश की गईं।

सबसे पहले, विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय स्वरूप को संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं की भरमार की ही तरह बहुपक्षीय समझौतों से संबंधित अनेक प्रस्तावों के कारण डब्ल्यूटीओ प्रणाली का आगे और भी अधिक विखंडन हो सकता है। दूसरा, सुधारों के बजाय डब्ल्यूटीओ को संभवतः पुनर्संतुलन की आवश्यकता है। यह आवश्यक है क्योंकि विकसित देशों द्वारा प्रायोजित कई सुधार प्रस्तावों के कारण विकासशील देशों में कृषि, औद्योगिक सब्सिडी, निवेश, डेटा, इत्यादि सहित कई खंडों में विकास प्रभावित हो सकता है। यही नहीं, डब्ल्यूटीओ प्रणाली विकसित देशों की एकतरफा कार्रवाई से निपटने में असमर्थ रही है। तीसरा, लागू करने योग्य नियमों को बनाने और विवाद निपटान व्यवस्थां में नई जान फूंकने पर अवश्य ही विशेष जोर होना चाहिए।

पैनल ने डब्ल्यूटीओ द्वारा आगे बढ़ाई जा रही एकल प्रतिबद्धता व्यवस्थाओं से जुड़ी चिंता और सब्सिडी एवं आईपीआर जैसे मुद्दों में निहित जटिलताओं पर भी चर्चा की। सदस्यों ने विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय और क्षमताओं में व्यापक अंतर को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूटीओ प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विकासशील देशों को दी गई विशेष एवं भिन्न (एसएंडडी) तरजीह से जुड़े प्रावधानों के स्वरूप और विकासशील देशों की उभरती जरूरतों के लिए आवश्यक धनराशि की ओर ध्यान दिलाया। इसे भी ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों को दी गई विशेष एवं भिन्न (एसएंडडी) तरजीह के साथ–साथ यहां तक कि क्षेत्रीय समझौतों में भी निहित इस तरह के प्रावधानों के लिए एक अलग नजरिया अपनाना आवश्यक हो सकता है। यह अफ्रीका के एलडीसी के लिए विशेष रूप से सच है जो क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ और भी अधिक मजबूती से एकीकृत करने की इच्छा रखते हैं। अफ्रीकी संदर्भ में वहां की अर्थव्यवस्थाओं के विविधीकरण के लिए नवोदित उद्योग के संरक्षण के संबंध में विशेष एवं भिन्न (एसएंडडी) तरजीह की आवश्यकता निश्चित रूप से चिंता का प्रमुख विषय है। इनमें से कई देश डब्ल्यूटीओ के कई विभागों में शीर्ष नेतृत्व पाने एवं निर्णय लेने में भागीदारी की इच्छा जताने के अलावा अपने यहां घटिया उत्पादों की डंपिंग जैसे मुद्दों से निपटने के लिए डब्ल्यूटीओ में मजबूत विवाद निपटान व्यंवस्था स्थापित करने की भी मांग कर रहे हैं।

आखिर में, इस ओर ध्यान दिलाया गया कि मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं की बढ़ती जरूरतों, आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और टीकों एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए जी20 इस मोड़ पर बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

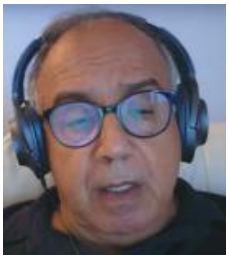

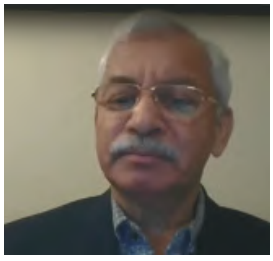

'क्रिस्पर' के लिए नोबेल पुरस्कार

'क्रिस्पर' पर उल्लेखनीय कार्य के लिए दो अग्रणी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से नवाजे जाने के बाद क्रिस्पर तकनीक जिस तरह से आम जनता और मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उसे ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने 29 अक्टूबर 2020 को 'क्रिस्पर के लिए नोबेल पुरस्कार' विषय पर वेबिनार आयोजित किया। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट्स (क्रिस्पर) दरअसल डीएनए अनुक्रमों के एक विशिष्ट परिवार या वर्ग को कहते हैं और इसका उपयोग जीनोम एडिटिंग में किया जाता है। इस साल रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से जेनिफर डॉडना और एमैनुएल चारपेंटियर को 'क्रिस्पर' पर उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए नवाजा गया जिसकी बदौलत ही इसका व्यापक उपयोग संभव हो पाया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में कई क्षेत्रों में शोध और इसके अनुप्रयोगों में 'क्रिस्पर' के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आरआईएस विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकियों के प्रभावों और निहितार्थों पर काम करता रहा है। इस व्याख्यान का आयोजन इसलिए किया गया, ताकि क्रिस्पर, स्वास्थ्य एवं कृषि में इसके अनुप्रयोगों और इस प्रौद्योगिकी के संचालन से जुड़े मुद्दों को आसानी से समझा जा सके। प्रोफेसर बी के थेल्मड, जेनेटिक्स विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, और मानव जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सदस्य ने पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता की। उन्होंने आनुवांशिक मानव जीनोम एडिटिंग के बारे में 'मानव जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग के क्लीनिकल उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग' की सिफारिशों और रिपोर्ट के आधार पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. देबज्योति चक्रबर्ती, सीएसआईआर – जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) ने बताया कि क्रिस्पर तकनीक कैसे विकसित हुई और आखिरकार यह क्या–क्या करने में सक्षम है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टेम सेल सहित थेरेपी और उपचारों की एक विस्तृत श्रृंखला में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बारे में बताया। सीएसआईआर की सिकल सेल एनीमिया (रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी) परियोजना की एक केस स्टडी का उल्लेख करते हुए उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे इस तरह की शारीरिक हालत का सटीक उपचार ढूंढने के लिए क्रिस्पर का उपयोग किया जा रहा है जिससे आदिवासी लोग व्यापक रूप से ग्रस्त रहते हैं। डॉ. एम. के. रेड्डी, ग्रुप लीडर, अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीजीईबी) ने चावल से जुड़े अपने विशिष्ट अनुसंधान का उदाहरण देते हुए कृषि क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग की सचित्र व्याख्या पेश की। इसके साथ ही उन्होंने इस बारे में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया कि किस तरह से चावल की पैदावार व्यापक रूप से बढ़ाने में 'क्रिस्पर' काफी मददगार साबित हो सकती है।

आईसीएमआर की जैवनैतिकता इकाई की प्रमुख डॉ. रोली माथुर ने सार्वजनिक समझ विकसित करने की जरूरत के साथ–साथ मानव स्वास्थ्य में इसके अनुप्रयोग के नियमन के लिए दिशा–निर्देश विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। जीन थेरेपी के लिए दिशा–निर्देश विकसित करने पर आईसीएमआर द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण भरोसा और लोगों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केवल तभी इस प्रौद्योगिकी को सहर्ष स्वीकार किया जा सकेगा। पैनल परिचर्चा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

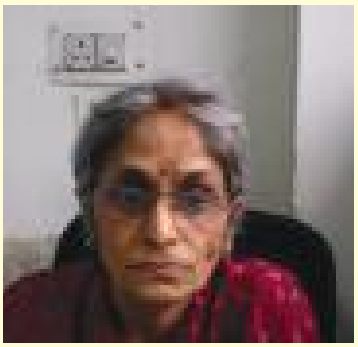

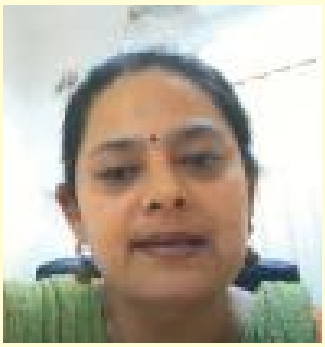
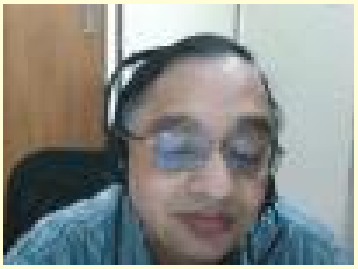
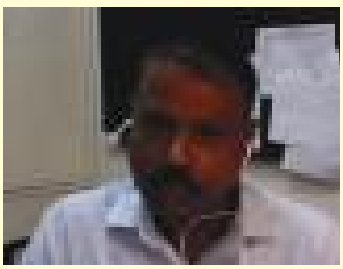

कोविड–19 से निपटने के लिए बहुपक्षीय उपाय: दक्षिण एशिया की ओर से परिप्रेक्ष्य

'कोविड–19 से निपटने के लिए बहुपक्षीय उपाय – दक्षिण एशिया की ओर से परिप्रेक्ष्य' विषय पर वेबिनार 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया। यह वेबिनार नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा आरआईएस, सतत विकास नीतिगत संस्थान (एसडीपीआई), श्रीलंका के नीतिगत अध्ययन संस्थान और व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया वॉच (एसएडब्ल्यूटीईई) के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी) के अध्यक्ष प्रोफेसर रहमान सोभन ने इसकी अध्यक्षता की।

कार्यक्रम की शुरुआत नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी) की कार्यकारी निदेशक डॉ. फहमीदा खातून के आरंभिक भाषण के साथ हुई। मुख्य प्रस्तुति श्री ओलिवियर कट्टानियो, इकाई के प्रमुख, नीतिगत विश्लेषण एवं रणनीति, विकास सहयोग निदेशालय, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी), और डॉ. देबाप्रिया भट्टाचार्य, प्रतिष्ठित फेलो, सीपीडी एवं अध्यक्ष, सदर्न वॉयस द्वारा दी गई। इसके बाद क्षेत्रीय साझेदारों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए: प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; डॉ. आबिद काइयूम सुलेरी, कार्यकारी निदेशक, सतत विकास नीतिगत संस्थान (एसडीपीआई), पाकिस्तान; डॉ. दशनी वीराकून, कार्यकारी निदेशक, श्रीलंका का नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस), श्रीलंका; और डॉ. पुष्पा शर्मा, कार्यकारी निदेशक, व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशिया वॉच (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल। क्षेत्रीय साझेदारों द्वारा अपने–अपने विचार व्यक्त करने के बाद परिचर्चा आयोजित की गई। इसके बाद डॉ. ए. बी. मिर्जा अजीजुल इस्लाम, कार्यवाहक सरकार के पूर्व सलाहकार, वित्त एवं नियोजन मंत्रालय ने विशेष भाषण दिया और श्री जॉर्ज मोरीरा डा सिल्वा, विकास सहयोग निदेशालय के निदेशक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने वीडियो संदेश भेजा। सीपीडी के अध्यक्ष प्रोफेसर रहमान सोभन ने समापन भाषण दिया।

पृष्ठ 8 से जारी....

'भारत में बी–20 वैश्विक संवाद' पर डिजिटल सम्मेलन

हितधारकों द्वारा पेश किए जाने वाले विचारों में सामंजस्य स्थापित करने में जुटा रहा है, ताकि नीति निर्माताओं के लिए उन्हें अत्यंत आसानी से समझना और जी20 के स्तर पर लागू करना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जी20 में टी20 (थिंक–टैंक) प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के अलावा आरआईएस इस संबंध में जी20 के मुद्दों पर *'द जी20 डाइजेस्ट'* नामक एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए सार्थक जानकारियां सृजित करने के तहत ही इस पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत डॉ. मोहन कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। बी20 सऊदी अरब के अध्यक्ष श्री यूसेफ अब्दुल्ला अल–बेन्यान ने कहा कि सऊदी अरब ने अपनी जी20 अध्यक्षता के दौरान कारोबार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और व्यापार व निवेश से संबंधित मुद्दों को सुलझाने को भी प्राथमिकता दी है।

माननीय श्री सऊद बिन मोहम्मद अल–सती, भारत में सऊदी अरब के राजदूत; श्री नौशाद फोर्ब्स, पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई एवं अध्यक्ष, सीआईआई की अंतर्राष्ट्रीय परिषद; और श्री चंद्रजीत बनर्जी, महानिदेशक, सीआईआई ने भी इस कार्यक्रम के दौरान अपने–अपने विचार व्यक्त किए।

भारत–श्रीलंका संबंध

आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र, आईसीडब्ल्यूए, पाथफाइंडर फाउंडेशन और एशियन कनफ्लुएंस ने 29 अक्टूबर 2020 को 'भारत–श्रीलंका संबंधः नई विश्व व्यवस्था में भारत–श्रीलंका संबंधों को मजबूत करना' विषय पर संयुक्त रूप से वर्चुअल (आभासी) संवाद आयोजित किया। डॉ. टी सी ए राघवन, महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने इसकी अध्यक्षता की। एशियन कनफ्लुएंस के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची दत्ता ने स्वागत भाषण दिया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और राजदूत बर्नार्ड गुनेटिलेके, अध्यक्ष, पाथफाइंडर फाउंडेशन ने आरंभिक भाषण दिए। एडमिरल जयनाथ कोलोमबेज (सेवानिवृत्त), विदेश सचिव, श्रीलंका ने मुख्य भाषण दिया।

पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता राजदूत, अशोक के. कांथा, निदेशक, चीनी अध्ययन संस्थान (आईसीएस), और श्रीलंका में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त ने की। डॉ. गणेशन विघ्नराज, वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, लंदन; प्रो. रोहन समरजीवा, संस्थापक अध्यक्ष, लिरनेशिया, कोलंबो; और श्री विश गोविंदसामी, समूह के प्रबंध निदेशक, सनशाइन होल्डिंग्स पीएलसी एवं उपाध्यक्ष, द सीलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स, कोलंबो इस अवसर पर श्रीलंका की ओर से मुख्य वक्ता थे। भारत की ओर से डॉ. समाथा मल्लेम्पति, रिसर्च फेलो, आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली; प्रो. बिस्वजीत नाग, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, दिल्ली; और श्री एम.एस. नेगी, वाइस–प्रेसीडेंट (ऋण), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), कोलंबो ने इन चर्चाओं की अगुवाई की।

माननीय श्री गोपाल बागले, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त, कोलंबो ने समापन भाषण दिया और डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस स्थित एआईसी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

आईसीडब्ल्यूए, आरआईएस, केएनडीए, और कीप के बीच द्विपक्षीय संवाद पर एमओयू का हस्ताक्षर समारोह

आईसीडब्ल्यूए और आरआईएस ने 22 अक्टूबर 2020 को आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कोरिया गणराज्य की कोरिया राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी (केएनडीए) और कोरिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान (कीप) के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। प्रो. वोंगी चोए (प्रमुख, आसियान–भारतीय अध्ययन केंद्र, केएनडीए) ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। डॉ. किम जून–ह्यूंग, कुलाधिपति, केएनडीए; डॉ. टी.सी.ए. राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए; डॉ. जंग सुंग चुन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कीप; और डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने भाषण दिए। इसके बाद एमओयू पर हस्ताक्षर किए

गए। राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन, कोरिया गणराज्य में भारत की राजदूत; और राजदूत शिन बोंगकिल, भारत में कोरिया गणराज्य के राजदूत ने विशेष भाषण दिए। खुली परिचर्चा के बाद डॉ. जोजिन जॉन, रिसर्च फेलो, आईसीडब्ल्यूए ने समापन भाषण दिया।

शेष पृष्ठ 1 से जारी....
नई विश्व व्यवस्था में भारत और अर्जेंटीना

चेतना में विशेष स्थान रखता है। अर्जेंटीना में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक योग विशेषज्ञों की मौजूदगी और बड़ी संख्या में योग स्कूलों को खोला जाना अपने आप में इस सच्चाई को अभिव्यक्त करता है।

वेबिनार में उद्घाटन और समापन सत्र सहित कुल तीन मुख्य सत्र थे। उद्घाटन सत्र को अर्जेंटीना में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, और सीआईपीपीईसी की कार्यकारी निदेशक डॉ. जूलिया पोमारेस ने संबोधित किया। राजदूत दिनेश भाटिया ने वेबिनार के संदर्भ के बारे में बताया और इसके साथ ही हमारे सामान्य सिद्धांतों, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, कूटनीति, रुचि व मूल्य में हमारे आपसी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी की दृष्टि से दोनों देशों के बीच हमारे मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला। इस दौरान दो रणनीतिक साझेदारों भारत और अर्जेंटीना के बीच के संबंधों की मौजूदा स्थिति और भविष्य के बारे में विचार–विमर्श किया गया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने डिजिटल दुनिया में नई विश्व व्यवस्था को सटीक स्वरूप देने और जी–20 की सऊदी अध्यक्षता के प्रति ब्यूनस आयर्स से आ रही दक्षिण–दक्षिण सहयोग से जुड़ी पूरी गाथा का विस्तार करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे साझा प्रयासों की सराहना की। डॉ. जूलिया पोमारेस ने अर्जेंटीना एवं भारत के बीच विकास सहयोग और वैश्विक दक्षिण में अनुसंधान संबंधी पहल में संभावित साझेदारी पर विशेष जोर दिया क्योंकि डिजिटलकरण से दोनों ही देशों के श्रम बाजार काफी प्रभावित होंगे।

'भारत–अर्जेंटीना द्विपक्षीय संबंध' पर आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता डॉ. टी. सी. ए. राघवन, महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने की। सत्र में पैनलिस्ट ये थेः प्रो. सुनंदा सेन, अर्थशास्त्र की पूर्व प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डॉ. मारिया फ्लोरेंसिया रूबियोलो, कोर्डोबा कैथोलिक विश्वविद्यालय – कॉनिकेट और डॉ. मैनुअल गोन्जालो, जनरल सरमिएंटो नेशनल यूनिवर्सिटी–यूएनडीईसी, और श्री बर्नाबे मलाकाल्जाल, क्विल्म्स नेशनल यूनिवर्सिटी – कॉनिकेट – टॉरक्वाटो डि टेला यूनिवर्सिटी ने भारत एवं अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग और कोविड काल के बाद व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की संभावनाओं पर आयोजित व्यापक परिचर्चा का संचालन किया। सत्र के दौरान द्विपक्षीय व्यापार के मौजूदा प्रवाह, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार में और भी अधिक विविधीकरण लाने की संभावनाओं तथा दोनों देशों के बीच समानता पर गौर किया गया, क्योंकि दोनों ही देश महामारी के दौरान कुछ वृहद आर्थिक संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। सत्र के दौरान कुछ प्राथमिकताओं के साथ–साथ विशेषकर व्यापार व निवेश और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) में सहयोग वाले फोकस क्षेत्र पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरान स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में केंद्रित व गहन सहयोग पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि प्रौद्योगिकी और तकनीकी व्यवधान विभिन्न देशों के सामने कई चुनौतियां उत्पन्न कर देते हैं, जिनसे निपटने के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र के पास देने के लिए संभवतः कुछ पर्याप्त नहीं है और निर्यात दायरे को व्यापक बनाना होगा और इसके साथ ही इसका स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार मांग बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और ऊर्जा चुनौतियां दोनों ही देशों के लिए चिंता का प्रमुख विषय हैं जिन पर और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः भारत और अर्जेंटीना के पास एक बेहतर स्थिति में पहुंचने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के जरिए समावेशिता को प्रोत्साहित करने के लिए आपस में हाथ मिलाने; एसटीआई सहयोग का सशक्तिकरण करने; और आपस में मिलकर काम करने हेतु बहुपक्षवाद का विस्तार करने के लिए व्यापक गुंजाइश है।

'भूमंडलीकरण, डिजिटलीकरण और अनुसंधान पहलः वैश्विक दक्षिण से सबक' विषय पर आयोजित दूसरे संवादात्मक सत्र की अध्यक्षता सुश्री इरेन ब्रांबिला, वितरण, श्रम एवं सामाजिक अध्ययन केंद्र ने की। इसमें चार पैनलिस्ट ये थेः डॉ. रजत कथूरिया, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद; डॉ. उर्वशी अनेजा, संस्थापक निदेशक, टैन्डम रिसर्च; डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस और श्री रामिरो अलब्रियू, आर्थिक विकास के वरिष्ठ शोधकर्ता, सीआईपीपीईसी। सभी वक्ताओं ने प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर विशेष जोर दिया और इसके साथ ही एआई

शेष पृष्ठ 14 पर जारी....

पृष्ठ 13 से जारी....

जैसी नई तकनीकों की क्षमता का उपयोग करने के तरीकों तथा एक समावेशी, सतत एवं न्यायसंगत समाज की अगुवाई करने में इसके विशिष्ट योगदान पर विचार–विमर्श किया। सत्र के दौरान भारत एवं अर्जेंटीना के वर्तमान विकास पथ पर फोकस किया गया और इसके साथ ही इस बारे में एक रोडमैप पेश किया गया कि आखिरकार कैसे और भी अधिक आत्मनिर्भर बनना संभव है एवं प्रौद्योगिकी किस तरह से उत्पादकता बढ़ा सकती है। आम तौर पर, बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाने संबंधी प्रतिकूल प्रभाव के लिए प्रौद्योगिकी को ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि इसमें सतत उपभोग और उत्पादन से जुड़ा सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता होती है। वक्ताओं ने इस बात पर चर्चा की कि हम आर्थिक विकास के लिए पारंपरिक क्षेत्र में नई जान कैसे डाल सकते हैं।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने 'कोविड काल के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत और अर्जेंटीना' विषय पर आयोजित तीसरे सत्र में एक प्रस्तुति दी। सत्र की अध्यक्षता श्री रिकार्डो कैरिसियोफी, आर्थिक विकास कार्यक्रम के वरिष्ठ शोधकर्ता, सीआईपीपीईसी ने की। इस दौरान अन्य प्रख्यात वक्ता ये थेः श्री जॉर्ज चेडिएक, पूर्व निदेशक, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण–दक्षिण सहयोग कार्यालय, प्रो. हर्ष वी पंत, अध्ययन निदेशक एवं प्रमुख, रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और सुश्री ग्लेडिस लेचिनी, रोसारियो नेशनल यूनिवर्सिटी – कोनिकेट। प्रो. चतुर्वेदी ने बहुपक्षवाद के मुद्दे पर प्रकाश डाला और वैश्विक दक्षिण के बीच मतभेद का मुद्दा उठाया। अतः बहुपक्षवाद के विचार पर नए सिरे से गौर करने का समय अब आ गया है। इसके साथ ही अधिक उत्तरदायी, अभिनव, रचनात्मक और ज्यादा सक्रियता वाली भागीदारी पर वैश्विक समझौता करने की जरूरत है। भारत और अर्जेंटीना को नैतिक सिद्धांतों पर फिर से अमल सुनिश्चित करने के लिए आपस में हाथ मिलाना चाहिए। प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि हमें एक–दूसरे के सांस्कृतिक जुड़ाव को समझने के लिए और भी ज्यादा सिद्धांतकारों या विचारकों की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक दक्षिण में और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना संभव हो सके।

अंतिम समापन भाषण माननीय डॉ. एस. जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री और माननीय श्री फेलिप सोला, अर्जेंटीना के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उपासना मंत्री ने दिए। श्री सोला ने हमारे पारंपरिक समर्थन और व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सहयोग एवं कूटनीति में लंबे समय तक चलने वाले रणनीतिक गठबंधन पर प्रकाश डाला। भारत और अर्जेंटीना की कई संयुक्त परियोजनाएं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष सहयोग समझौतों, ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था, आईटी, जैव–प्रौद्योगिकी, कृषि–प्रौद्योगिकी, इत्यादि के क्षेत्र में हैं, क्योंकि दोनों ही देशों का अत्यंत लंबा शाश्वत साझा इतिहास रहा है और उनमें एक–दूसरे की संस्कृति के लिए आत्मीयता एवं सम्मान है। अतः दोनों ही राष्ट्र आपसी संबंधों को और भी अधिक प्रगाढ़ कर सकते हैं।

शेष पृष्ठ 1 से जारी....

महामारी के बाद हिंद महासागर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग

विश्व अर्थव्यवस्था के लिए रोल मॉडल बनते जा रहे हैं।

इन सभी तथ्यों के मद्देनजर आरआईएस ने आईओआरए सचिवालय के सहयोग से 25 नवंबर 2020 को 'महामारी के बाद हिंद

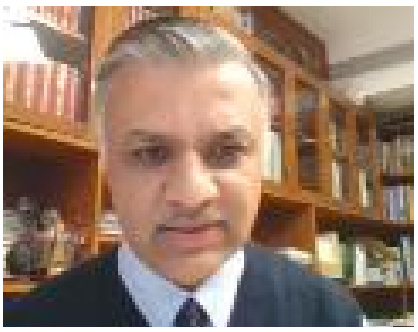

महासागर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगः आगे की राह' विषय पर एकदिवसीय वेबिनार आयोजित किया। माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने इसके सदस्य देशों के बीच और इस क्षेत्र के अन्य समूहों के साथ सहयोग बढ़ाकर आईओआरए को सुदृढ़ करने की भारतीय प्रतिबद्धता पर विशेष जोर दिया, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 2011 में आईओआरए की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती भू–रणनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसमें नई जान फूंकने और इसे सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत सक्रियतापूर्वक काम किया था। पिछले कुछ वर्षों में हम नियमित बैठकें कर, नई संरचनाओं का निर्माण करके, सचिवालय की दक्षता बढ़ाकर, संवाद साझेदारों के साथ अधिक–से–अधिक सहयोग बढ़ाकर, और आईओआरए के विभिन्न प्राथमिकता वाले एवं परस्पर संबंधित क्षेत्रों में ठोस पहल करके आईओआरए को मजबूत करने के मार्ग पर और आगे बढ़ गए हैं। वैसे तो सहयोग के कई क्षेत्र हैं, लेकिन मंत्री ने इस क्षेत्र में पर्यटन में नए प्राण डालने के लिए एक अहम कदम के रूप में पर्यटन उद्योग में सुधार या बेहतरी बहाल

करने और आयुर्वेद एवं वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत को आईओआरए के भीतर ब्लू इकोनॉमी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अधिक–से–अधिक काम किए जाने में भी काफी लाभ नजर आ रहा है। प्रदूषण, विशेषकर प्लास्टिक कचरे एवं तेल रिसाव के खतरे और अवैध, गुप्त और अनियंत्रित ढंग से मछली पकड़ने जैसे संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से रचनात्मक समाधानों और लोगों की भागीदारी के जरिए निपटने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि एक विविध एवं सुदृढ़ हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिए

हमारी क्षेत्रीय संरचना को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस के लिए भी हमारी आपस में जुड़ी दुनिया में कोविड–19 महामारी से निपटने में बहुपक्षवाद की केंद्रीयता को रेखांकित किया। उन्होंने *'ब्लू इकोनॉमी इनसाइट'* पत्रिका का विमोचन भी किया। माननीया डॉ. नोमव्यूमयो नोकवे, महासचिव, आईओआरए सचिवालय ने विशेष

भाषण दिया। राजदूत अनिल सुकलाल, उप महानिदेशक, दक्षिण अफ्रीका; राजदूत खुर्शीद आलम, सचिव, समुद्री मामले, बांग्लादेश, और सुश्री रीनात संधू, अपर सचिव (आईपी, दक्षिण और ओशिनिया), विदेश मंत्रालय और विभिन्न आईओआरए देशों के 13 तकनीकी विशेषज्ञों ने इस वेबिनार में भाग लिया। आरआईएस की ओर से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक; और प्रोफेसर एस. के. मोहंती ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

माननीया डॉ. नोकवे ने आईओआरए सचिवालय द्वारा पिछले पांच वर्षों में नीली अर्थव्यवस्था को दिए गए विशेष महत्व को रेखांकित किया जिसमें मॉरीशस, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में नीली अर्थव्यवस्था पर

आयोजित की गई उच्च स्तर की तीन मंत्रिस्तरीय बैठकें भी शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में स्थिरता की हिफाजत करते हुए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान महासागरों एवं समुद्री संसाधनों का दोहन करने, आर्थिक विकास की गति तेज करने, रोजगार सृजन और नवाचार के लिए की गई है। इसके साथ ही पहली बैठक में जकार्ता समझौते को अपनाया गया, जिसमें समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और शिक्षा के एक प्रमुख स्रोत के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए आईओआरए की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। इसके अलावा, उन्होंने नीली अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में प्लास्टिक से जुड़े प्रदूषण, एसडीजी और अन्य क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया। मानव एवं वित्तीय संसाधनों दोनों ही के लिए आईओआरए के सदस्य देशों के बीच और संवाद साझेदारों के मध्य सहयोग बढ़ाना सर्वाधिक आवश्यक है, ताकि कोविड–19 से उत्पन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटा जा सके। मानव और वित्तीय दोनों ही संसाधन इस दिशा में अनुकूलन के साथ–साथ इसमें कमी सुनिश्चित करने की चुनौतियों का सामना करने और तूफान से सुरक्षित ढंग से निकल जाने के लिए आवश्यक हैं।

सुश्री संधू ने सरकार द्वारा आईओआरए के लिए हाल ही में की गई कुछ पहलों पर प्रकाश डाला। विशेषकर वर्ष 2011 में भारत की अध्यक्षता के दौरान व्यापक पुनरुद्धार के साथ–साथ आईओआरए की प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने को ही सर्वाधिक अहमियत दी गई। वर्ष 2011 में मंत्रिपरिषद की 11वीं बैठक में एक भारतीय प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले छह क्षेत्रों की पहचान की गई थी, ताकि आने वाले वर्षों में आईओआरए के सदस्य देशों के बीच सहयोग पर फोकस किया जा सके। आपदा जोखिम का प्रबंधन, और अकादमिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग जैसे आईओआरए के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अग्रणी देश के रूप में भारत ने आईओआरए के सदस्य देशों की क्षमताओं को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर ठोस काम किया है। भारत ने आईओआरए विशेष कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, आईओआरए सचिवालय को मजबूत करने के लिए इस वर्ष सितंबर में भारत की ओर से एक आईटी विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति की है, संवाद साझेदारों के साथ

आईओआरए के जुड़ाव को सही स्वरूप देने, आईओआरए की संस्थागत रूपरेखाओं को मजबूत करने, अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ आईओआरए के जुड़ाव को बढ़ावा देने, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग करने, सूचना समेकन केंद्र 'आईएफसी–आईओआर' के साथ समुद्री जानकारियां साझा करने, और आखिर में आईओआरए क्षेत्र के लिए एचएडीआर दिशा–निर्देशों को तैयार करने में अगुवाई की है।

दो तकनीकी सत्रों में उपस्थित पैनलिस्टों ने आईओआरए क्षेत्रीय सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए विभिन्न मुद्दों और प्राथमिकताओं पर चर्चाएं कीं। विचार–विमर्श के दौरान समुद्री सुरक्षा, मत्स्य पालन, नीली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय महासागर ऊर्जा, समुद्री प्रौद्योगिकियों, ऐतिहासिक और समुद्री जुड़ाव, इत्यादि को व्यापक रूप से कवर किया गया। इस तरह के सत्रों में विचार–विमर्श के दौरान विभिन्न सिफारिशें उभर कर सामने आती हैं, ताकि आगे की कार्रवाई करने के साथ–साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

पृष्ठ 6 से जारी....
इब्सा में बढ़ता सहयोगः प्रमुख क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य

लोगों की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में महत्वपूर्ण अध्ययन शामिल हैं जिन्हें नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं द्वारा संदर्भित किया जाएगा।

श्री छाबड़ा के संबोधन के बाद इब्सा फेलो ने अपने–अपने शोध पत्रों में दिए गए प्रमुख तर्क पेश किए। ब्राजील की सुश्री एलिस वीरिया डॉस सैंटोस ने इब्सा देशों के बीच मतदान व्यवहार एवं पारस्परिक समर्थन का विश्लेषण किया, और इसके साथ ही यह दलील दी कि उनके मतदान व्यवहार और पारस्परिक समर्थन में व्यापक सामंजस्य है। उन्होंने पारस्परिक समर्थन में सामंजस्य एवं असमानता वाले क्षेत्रों का आकलन किया, और संकेत दिया कि इब्सा को कोई खास पारस्परिक समर्थन नहीं मिला है, और विशिष्ट मुद्दों पर इनके समर्थन को मजबूत करने की व्यापक प्रवृत्ति को देखते हुए आपसी हित के विषयों, विशेषकर स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा चूंकि इब्सा मजबूत लोकतांत्रिक बुनियाद पर आधारित है, इसलिए यह बहुपक्षवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ब्राजील की ही रहने वाली सुश्री पोलियाना बेलिसारियो जोरजल ने एक अवरोध के रूप में पेटेंट का उपयोग करके इब्सा जैव विविधता संरक्षण का आह्वान किया, ताकि कानूनी तौर पर उनके प्राकृतिक आनुवांशिक संसाधनों की रक्षा की जा सके। उन्होंने इब्सा के लिए दो दृष्टिकोणों को अपनाने का तर्क दिया, ताकि उनकी सामान्य बहुपक्षीय संस्थागत रूपरेखा को सुदृढ़ किया जा सके। इनमें राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के बीच सामंजस्यपूर्ण दिशा–निर्देश और उनके राष्ट्रीय नियमों में सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) आवश्यकताओं के लिए समान मानक कानूनों को लागू करना शामिल हैं। अनुसंधान संस्थानों के बीच इब्सा सहयोग को व्यापक बनाने; और आनुवांशिक डेटा की प्राप्ति, पहुंच एवं लाभ साझा करने के लिए एक व्यापक विश्लेषणात्मक डेटा की आवश्यकता दरअसल आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण हेतु आपस में समन्वय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दक्षिण अफ्रीका की सुश्री कारिन क्रिट्जिगर ने अक्षय ऊर्जा की दिशा में प्रगति में रूफ–टॉप सौर की भूमिका पर इब्सा देशों के बीच सहयोग में सामंजस्य, मतभेद और इसकी गुंजाइश का विश्लेषण किया। इस प्रस्तुतकर्ता ने इब्सा देशों में नवीकरणीय ऊर्जा की गुंजाइश को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और शुल्क दरों (टैरिफ) की मजबूत संभावनाओं पर विशेष जोर दिया।

एक भारतीय जानकार श्री कमलेश गोयल ने स्वास्थ्य सेवा में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अनुसंधान एवं विकास, पारंपरिक चिकित्सा के पेटेंट संरक्षण, और संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सामंजस्य, एवं सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।

भारत की ही रहने वाली सुश्री राबिया खातुन ने बैंकिंग सेवाओं के व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया और उन सिफारिशों का एक समूह प्रस्तुत किया जो इब्सा देशों में इसकी गुंजाइश को मजबूत करने और आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं।

डॉ. बीना पांडे, अनुसंधान सहयोगी, आरआईएस ने इब्सा फंड के माध्यम से की गई विभिन्नं पहलों के अनूठे स्वरूप एवं दायरे का अध्ययन किया, और इसके साथ ही विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, ऋण परियोजनाओं, कृषि, रोजगार एवं आजीविका, युवाओं की सहभागिता, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और एड्स की समस्याओ से निपटने के लिए क्षमता निर्माण में इसके विशेष महत्व को रेखांकित किया।

माननीय श्री आंद्रे अरन्हा कॉररिया डो लैगो, राजदूत, ब्राजील का दूतावास, नई दिल्ली ने कहा कि यह रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है और संबंधित शोध पत्र इब्सा के एजेंडे को उत्कृष्ट एवं समृद्ध बनाने में काफी मदद करेंगे। उन्होंने नई सड़कों या क्षेत्रों को खोलने में इब्सा की विशिष्ट अहमियत को स्वीकार किया जहां इब्सा देश सहयोग और गठबंधन के माध्यम से एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और जिसके लिए तीन देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी काफी मायने रखती है। उन्होंने कहा कि इब्सा ऐसी प्रथम बहुपक्षीय व्यवस्थां है जिसमें ब्राजील ने सहभागिता की है और इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत और ब्राजील के बीच सहयोग के परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तीनों ही देश इब्सा के एजेंडे को मजबूत करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्होंने सहयोग के जरिए हासिल किए गए शानदार परिणामों और भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने आरआईएस के ठोस प्रयासों के साथ–साथ इसके द्वारा निभाई गई अद्भुत भूमिका को सराहा।

श्री सिबुसिसो एनडेबेल, राजदूत, दक्षिण अफ्रीका का दूतावास, नई दिल्ली ने इब्सा फंड के लिए दक्षिण अफ्रीका की वित्तीय प्रतिबद्धता और उसके द्वारा इब्सा एवं इसकी पहलों को दिए जा रहे विशेष महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अतीत में इब्सा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के साथ–साथ चुनौतियों को स्वीकार करने और संबंधित देशों के बीच अनुभवों के अकादमिक आदान–प्रदान में इसकी अहम भूमिका को सराहा तथा विभिन्न लोकतंत्रों के गठबंधन की एकजुट मजबूत आवाज के रूप में इब्सा का अनुमोदन किया।

इस अवसर पर तंजानिया के उच्चायुक्त माननीय बाराक हरान लुवंदा की मौजूदगी की ओर सबका ध्यान गया और फिर उनसे अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने आरआईएस को बधाई दी और इब्सा के अथक प्रयासों को सराहा। श्री छाबड़ा ने समापन भाषण दिया। डॉ. मोहन कुमार और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने भावी आयोजनों को लेकर उम्मीदें जताने एवं इब्सा सहयोग को और भी अधिक मजबूत करने पर अपना विजन साझा किया। प्रतिष्ठित अतिथियों और वर्चुअल लॉन्चिंग समारोह के प्रतिभागियों के समापन संबोधन के बाद डॉ. सब्यसाची साहा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

सतत विकास हेतु उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियां

दिल्ली VI की ओर अग्रसर होने पर वेबिनार श्रृंखला के तहत नेस्ट, यूएनडीपी, आरआईएस और अनाहुआक, मेक्सिको ने 18 दिसंबर 2020 को 'लैटिन अमेरिका में सतत विकास हेतु उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणीय साझेदारियों' पर संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया। वर्ष 2013 से ही दक्षिणी प्रदाताओं के सम्मेलन (दिल्ली प्रोसेस) में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत संबंधित हितधारकों के बीच एसएससी से जुड़े मुद्दों और उभरती चुनौतियों पर चर्चाएं होती रही हैं।

एसएससी से जुड़ी अनेक वार्षिक बैठकें और विशेष चर्चाएं दरअसल विशेषज्ञों, प्रोफेशनलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अपने–अपने अनुभवों एवं ज्ञान को साझा करने का अनूठा मंच बन गईं। वर्तमान कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ जुड़ाव एवं संपर्क बनाना, अपने हितों की पूर्ति को बढ़ावा देना, और एसएससी संबंधी प्रयासों से जुड़ी चिंताओं को दूर करना था, ताकि वर्तमान कोविड–19 संकट से बेहतर ढंग से उबरने के लिए विभिन्न देशों को आवश्यक सहयोग मिल सके।

उत्कृष्ट '1978 ब्यूनस आयर्स कार्य योजना' में कामयाबी पाने की आकांक्षा रखते हुए 'दक्षिणीय सहयोग पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन (बीएपीए 40)' ने अंततः इस मुख्य प्रश्न का हल सुझाने का मंच उपलब्ध कराया: सतत विकास में दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) का ठोस योगदान क्या है? मुख्य चुनौती यह आकलन करना है कि क्या एसएससी कार्यक्रम और परियोजनाएं विकासशील देशों की गरीबी मिटाने, असमानता घटाने एवं उच्च मूल्य वाली अधिक–से–अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ा रही हैं (अर्थात एसडीजी2: 'शून्य भुखमरी', एसडीजी8: 'उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास' और एसडीजी17: 'लक्ष्यों के लिए साझेदारियां')। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और डॉ. सांद्रा सोसो, उप–निवासी प्रतिनिधि, यूएनडीपी मेक्सिको के आरंभिक भाषणों के साथ हुई। इसके बाद 'सतत विकास हेतु उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणीय साझेदारियां: चुनौतियां और अवसर' विषय पर सत्र आयोजित किया गया।

मुख्य वक्ता ये थे: डॉ. गेब्रियल टेरेस, कार्यकारी निदेशक के सलाहकार, एमेक्ससिड; डॉ. पाउलो एस्टेवेस, ब्रिक्स नीतिगत केंद्र के निदेशक; डॉ. मार्टिन रिवेरो, सामाजिक सामंजस्य एवं एसएससी इकाई के समन्वयक, एसईजीआईबी; और डॉ. लिडिया फ्रॉम सीईए, कार्यकारी निदेशक, मेसोअमेरिकन एकीकरण एवं विकास परियोजना। डॉ. कार्लोस कोर्टेस जिया, एमेक्ससिड–यूएनडीपी सहयोग कार्यक्रम के समन्वयक, यूएनडीपी मेक्सिको इस अवसर पर चर्चाकर्ता एवं संचालक थे।

पैनलिस्टों ने संबंधित क्षेत्र में एसएससी संबंधी अभिनव दृष्टिकोणों के तहत लैटिन अमेरिका में सतत विकास हेतु उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने में एसएससी के योगदान वाले ठोस उदाहरणों और बिना शर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों की चुनौतियों एवं अवसरों को साझा करने पर केंद्रित किया। डॉ. जॉर्ज ए. पेरेज–पिनेडा, नेस्ट मेक्सिको/यूनिवर्सिडाड अनाहुआ मेक्सिको ने समापन भाषण दिया।

बीएनपीटीटी की पांचवीं बैठक

नीतिगत थिंक टैंकों के बिम्सटेक नेटवर्क (बीएनपीटीटी) की वर्चुअल पांचवीं बैठक आरआईएस द्वारा 21–22 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई। इस बैठक में बिम्सटेक के सात सदस्य देशों के थिंक टैंकों के 22 प्रतिनिधियों और बिम्सटेक सचिवालय के सात पदाधिकारियों ने भाग लिया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने बैठक की अध्यक्षता की। सुश्री रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत ने मुख्य भाषण दिया। बिम्सटेक सचिवालय के महासचिव तेनजिन लेकफेल ने हाल के वर्षों में बिम्सटेक की उपलब्धियों पर विशेष भाषण दिया और उन प्राथमिकताओं एवं पहलों को साझा किया जिन पर जल्द ही अमल किया जाना है।

इस बैठक के दौरान वर्ष 2018 में भूटान के थिंपू में आयोजित बीएनपीटीटी की चौथी बैठक में घोषित निर्णयों और प्रतिबद्धताओं की दिशा में हुई प्रगति का जायजा लिया गया। इस क्षेत्र में कोविड–19 से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों और बिम्सटेक क्षेत्र में आर्थिक बेहतरी के लिए रोडमैप पर फोकस किया गया। जहां एक ओर बिम्सटेक सहयोग के लिए विभिन्न सेक्टरों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेष सेक्टरों और मुद्दों को वर्ष 2021 में होने वाले पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इनमें बिम्सटेक एफटीए वार्ताओं का जल्द समापन करना, कुछ विशेष सेक्टरों में क्षेत्र के भीतर व्यापार की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेक्टर–वार मूल्य श्रृंखलाओं पर विशेष जोर देने की आवश्यकता, स्वास्थ्य क्षेत्र एवं चिकित्सा उपकरणों में वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक जैसे उभरते सेक्टर, इत्यादि शामिल हैं।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी की अगुवाई वाले आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल में प्रो. एस. के. मोहंती, प्रो. प्रबीर डे, प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. प्रियदर्शी दाश, डॉ. सब्यसाची साहा, डॉ. के. रवि श्रीनिवास, सुश्री प्रतिवा शॉ, सुश्री पंखुरी गौड़ और सुश्री सभ्या राय सहित 10 संकाय सदस्य शामिल थे। आरआईएस की टीम ने बिम्सटेक सहयोग एजेंडे के दायरे एवं विविधीकरण के साथ–साथ बैठक के अन्य खंडों में सक्रिय योगदान के अलावा आगामी पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए प्राथमिकताओं एवं सिफारिशों पर भी मेजबान संस्थान की प्रस्तुति दी।

31वां स्टिप फोरम व्याख्यान

31वां स्टिप फोरम व्याख्यान प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, डीएसटी द्वारा 17 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया। इस सार्वजनिक व्याख्यान की थीम यह थीः 'निडर नई दुनिया में विज्ञान का चमत्कार'। इस आयोजन की अध्यक्षता डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस ने की। डॉ. पूर्णिमा रूपल, निदेशक, सीईएफआईपीआरए, और डॉ. आर. रमणन, मिशन निदेशक, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग भी इस आयोजन के दौरान उपस्थित थे।

व्याख्यान प्रगति पर है जिसका यह स्क्रीनशॉट है

अपने अत्यंत दूरदर्शी संबोधन में प्रो. आशुतोष शर्मा ने भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहु–विषयक और समस्या–केंद्रित दृष्टिकोण के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि एसटीआई का भविष्य दरअसल विभिन्न प्रौद्योगिकी धाराओं में सामंजस्य के बारे में है। प्रो. आशुतोष शर्मा ने कहा, 'कोविड–19 ने हमें यह याद दिलाया है कि विघटनकारी बदलाव बेहद तीव्र गति से हो रहे हैं। हम आज एक निडर दुनिया में रह रहे हैं क्योंकि हमें बदलाव से निपटना ही होगा। नई दुनिया के बदलावों से निपटने के लिए हमें प्रौद्योगिकी की मांगों को पूरा करने की जरूरत है।'

उन्होंने हमारे एसटीआई और शिक्षा परिवेश को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा, 'उद्योग 4.0 दरअसल डेटा, सूचनाओं और ज्ञान के प्रवाह को नियंत्रित करने के बारे में है। सूचना और ज्ञान को साझा करना ही आने वाले हर समय के लिए भावी दिशा तय करेगा।'

प्रो. शर्मा ने एसटीआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की अनिवार्यता जताई। इतना ही नहीं, प्रो. शर्मा ने आत्मनिर्भरता के तीन पहलुओं यथा आत्म विश्वास, आत्म सम्मान और आत्म चिंतन को प्रस्तुत किया।

पृष्ठ 2 से जारी....
'वैश्विक स्तर पर आर्थिक बेहतरी....

लेकिन कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से बड़े पैमाने पर अनिश्चितता का माहौल बन गया है। मौजूदा संकट की पहली लहर के बाद से ही निजी निवेश के एक तरह से रुक जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे उत्पादकता के साथ–साथ विकास भी प्रभावित होगा, श्रम बाजार में युवाओं के एकीकरण में देरी होगी, वैश्विक मांग में कमी आएगी, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग कम हो जाएगा तथा विकास पर आगे और भी अधिक प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन और खुदरा (रिटेल) क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि इस वजह से लाखों लोग फिर से गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि संरक्षणवाद में वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निरंतर भारी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि बढ़ते ऋण भार और इससे जुड़े बैंकों के वित्तीय जोखिम की वजह से देश में आर्थिक बेहतरी की गति कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने बताया कि ऋण संचय और कर्ज भार में बढ़ोतरी के साथ–साथ आय की धीमी वृद्धि दर के कारण काफी कर्ज बांट चुके ऋणदाताओं की कॉरपोरेट ऋण उपलब्धता घटती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2020 में बैंकों के फंसे कर्जों में भारी वृद्धि होने के कारण बैंकों की ऋण देने की इच्छा और क्षमता घट जाने की आशंका है।

श्री पिनाउड ने कहा कि आने वाले वर्ष में कॉरपोरेट दिवालियेपन की सुनामी आने का अंदेशा है। उन्होंने यह भी कहा कि ढांचागत समस्याओं के साथ–साथ कंपनियों के सामने आने वाली समस्याओं को भी दूर करने के लिए एक सुव्यवस्थित दिवाला व्यवस्था और दिवालियापन कानून सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इटली की जी20 और उसके द्वारा 3पी (पीपल, प्लैनट, प्रोस्पेरिटी) यानी लोग, धरती एवं समृद्धि को प्राथमिकता देने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे असमानताओं से निपटने, समान अवसरों को बढ़ावा देने, पेरिस समझौते एवं एसडीजी से संबंधित प्रतिबद्धताओं को लागू करने, विकास एवं बेहतर जीवन स्तर के वाहकों के रूप में नई तकनीकों एवं डिजिटल बदलावों को बढ़ावा देने, और सुदृढ़ता को प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिलेगी। यही नहीं, जी20 अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी एवं श्रम संसाधनों को फिर से आवंटित करने और एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के जरिए लोगों को आवश्यक सहयोग देने के साथ–साथ सक्रिय श्रम

पृष्ठ 20 पर जारी....

नीतिगत वार्ता

पृष्ठ 19 से जारी....

बाजार नीतियां पेश करने की आवश्यकता है जिनमें कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हों। श्री पिनाउड ने कहा कि निरंतरता और सुदृढ़ता को फिर से सुनिश्चित करने में बहुपक्षवाद अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि इन चुनौतियों में अनगिनत सीमा पार संबंधी आवश्यकताएं निहित हैं।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि इस साल सऊदी अरब में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों को आगे बढ़ाने के अलावा कौशल विकास और बेहतरीन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर फोकस करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर राजदूत डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस, और दीप कपूरिया, चेयरमैन, हाई–टेक कंपनी समूह एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति पर सीआईआई की राष्ट्रीय समिति के सह–अध्यक्ष ने भी अपने–अपने विचार व्यक्त किए। आरआईएस दरअसल जी20 पर टी20 (थिंक–टैंक) प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के अलावा वर्ष 2022 में भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए अत्यंत उपयोगी जानकारियां सृजित करने के प्रयासों के तहत जी20 मुद्दों पर एक द्विमासिक पत्रिका *'जी20 डाइजेस्ट'* का प्रकाशन करता रहा है।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- 27 दिसंबर 2020 को भारतीय आर्थिक संघ द्वारा आयोजित आईईए (ऑनलाइन) के 103वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण दिया।
- 23 दिसंबर 2020 को विजनाना भारती (विभा) के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) में 'जी20, ब्रिक्स और एससीओ की भारतीय अध्यक्षता के दौरान कूटनीति के लिए विज्ञान एजेंडा तय करना' विषय पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 23 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा 'भारत के एफटीए (प्रदर्शन, वार्ताओं की स्थिति और आगे की राह)' विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 19 दिसंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से माननीया वित्त मंत्री के साथ आयोजित अर्थशास्त्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 15 दिसंबर 2020 को एसडीपीआई, यूएन एस्कैप और एसडीजी पर दक्षिण एशिया नेटवर्क द्वारा 'कोविड–19 काल में सतत विकास' विषय पर आयोजित 23वें सतत विकास सम्मेलन के दौरान 'एसडीजी की प्राप्ति में तेजी लाना और दक्षिण एशिया में कोविड–19 महामारी से बेहतर ढंग से आर्थिक बहाली' पर पैनल की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया।
- 8 दिसंबर 2020 को दक्षिण–दक्षिण वैश्विक विचारकः एसएससी के लिए थिंक टैंक नेटवर्क के वैश्विक गठबंधन के लिए यूएनओएसएससी द्वारा आयोजित संचालन समिति की चौथी बैठक में भाग लिया और दक्षिणी थिंक टैंकों के नेटवर्क (नेस्ट) पर अपने विचार व्यक्त किए।
- 4 दिसंबर 2020 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयुष मंत्रालय के हितधारकों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
- 4 दिसंबर 2020 को 'व्यवधान से निपटनाः कोविड दौर में आर्थिक विकास पर नए सिरे से विचार करना' विषय पर एशिया–प्रशांत फोरम की बैठक में 'क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण' पर आयोजित सत्र को संबोधित किया।
- 3 दिसंबर 2020 को 'वैश्विक समाधान पहल – शहरीकरण (और अवसंरचना): कोविड–19 से सतत रूप से निपटना' विषय पर आयोजित सम्मेलन के दौरान ''बेहतर भविष्य का निर्माण करनाः एक नई सतत अर्थव्यवस्था की अवसंरचना, बदलते बहुपक्षीय क्रम में शहर' पर आयोजित समाधान सत्र में मुख्य वक्ता थे।
- 3 दिसंबर 2020 को 'दक्षिण एशिया में कोविड–19 से सतत और मजबूत आर्थिक बेहतरी को बढ़ावा देने पर एसडीजी' पर चौथे दक्षिण एशिया फोरम की वर्चुअल बैठक में भाग लिया और यूएन एस्कैप एवं मालदीव सरकार द्वारा 'वैश्विक, क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय साझेदारियों का उपयोग करना और दक्षिण एशिया में एसडीजी की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए कार्यान्वयन के साधनः वित्त, प्रौद्योगिकी, डेटा और सांख्यिकी (एसडीजी17)' पर संयुक्त रूप से आयोजित गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया।
- 25 नवंबर 2020 को यूएनडीपी की नई रणनीतिक योजना 2022–2025 पर यूएनडीपी के प्रशासक श्री अचिम स्टीनर के साथ परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 24 नवंबर 2020 को 'भारत और – भविष्य का ध्यान करना – समकालीन

वास्तविकताएं एवं उभरती संभावनाएं, तीसरी भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस –प्प्) पहल' पर आईसीडब्ल्यूए के वेबिनार में भाग लिया और ''एजेंडा 2063 एवं भारत अफ्रीका विकास साझेदारी को परखना' विषय पर आयोजित सत्र प्प् को संबोधित किया।

- 24 नवंबर 2020 को विकास केंद्र, ओईसीडी द्वारा ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भविष्य' विषय पर आयोजित विशेषज्ञों के कार्यदल के ऑनलाइन प्रथम विचार मंथन सत्र में भाग लिया।
- 10 नवंबर 2020 को आयोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर जापान–भारत समिति की 10वीं बैठक के दौरान 'एसडीजी के लिए एसटीआई में भारत–जापान सहयोग' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 5 नवंबर 2020 को जर्मन विकास संस्थान द्वारा बीएमजेड स्थिति पत्र 'ग्लोबल पार्टनर्स' के लिए एमजीजी चिंतन समूह पर आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में भाग लिया।
- 28 अक्टूबर 2020 को सीआईडीजीए/सीआईडीआरएन द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग ज्ञान, शासन और प्रथा' विषय पर आयोजित वेबिनार के दौरान 'अंतर्राष्ट्रीय विकास संरचना के पुनर्निर्माण में दक्षिणीय सहयोग और त्रिपक्षीय सहयोग की भूमिका' विषय पर खुली परिचर्चा में भाग लिया।
- 23 अक्टूबर 2020 को ब्रिक्स अनुसंधान पर राष्ट्रीय समिति, रूस और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा ब्रिक्स अकादमिक फोरम में आयोजित सम्मेलन के दौरान 'विकास के लिए बेहतरीन और सुदृढ़ बुनियादी ढांचा – भारत का हालिया अनुभव' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 22 अक्टूबर 2020 को आईसीडब्ल्यूए द्वारा भारत गणराज्य के आईसीडब्ल्यूए एवं आरआईएस और कोरिया गणराज्य के केएनडीए एवं कीप के बीच द्विपक्षीय संवाद से जुड़े एमओयू पर आयोजित हस्ताक्षर समारोह के दौरान विशेष भाषण दिया।
- 15 अक्टूबर 2020 को आईसीएसएसआर द्वारा 'भारत और फिलीपींस के कोविड–19 से निपटने के तरीकों को परखना' विषय पर आयोजित वेबिनार के दौरान 'कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए भारत के नीतिगत उपाय' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 अक्टूबर 2020 को ब्रिक्स इंटरनेशनल स्कूल, ब्रिक्स अनुसंधान पर राष्ट्रीय समिति, रूस और ब्रिक्स रूस 2020 द्वारा ब्रिक्स इंटरनेशनल स्कूल 2020 – ब्रिक्स युवा मार्गदर्शकों के लिए प्रतियोगिता के दौरान 'महामारी काल के बाद वैश्विक शासन और ब्रिक्स सहयोग के लिए निहितार्थ' विषय पर आयोजित सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 6 अक्टूबर, 2020 को इस्टिट्यूटो अफरी इंटरनेशनली (आईएआई) द्वारा 'जी20 की इतालवी अध्यक्षता की ओरः कोविड–19 काल के बाद जी20 एजेंडे के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को फिर से तय करना' विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता थे।

प्रो. एस.के. मोहंती

- 27 दिसंबर 2020 को आयोजित 103वें ऑनलाइन वार्षिक सम्मेलन में भारतीय आर्थिक संघ (आईईए) में 'आर्थिक बेहतरीः प्रमुख क्षेत्रों में स्थिति और चुनौतियां' विषय पर आयोजित सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और परिचर्चा में भाग लिया।
- 23 दिसंबर 2020 को नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा 'भारत के एफटीए (प्रदर्शन, वार्ताओं की स्थिति और आगे की राह)' विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया और 'भारत के एफटीए की प्रभावकारिताः बहस में शामिल होना' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 दिसंबर 2020 को अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग का अनुसंधान संस्थान (आरआईईटीआई), मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, भारत द्वारा आयोजित एमपी–आईडीएसए–आरआईईटीआई वेब सेमिनार में एक मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और 'भारत के बदलते आयाम – जीवीसी क्षेत्र में व्यापार और निवेश की जापान आर्थिक संबंध संभावना' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 27 नवंबर 2020 को बर्टेल्समैन स्टिफ्टंग, जर्मन वैश्विक एवं क्षेत्र अध्ययन संस्थान (जीआईजीए), अंतर्राष्ट्रीय व सुरक्षा मामलों के लिए जर्मन संस्थान (एसडब्ल्यूपी) और जर्मन संघीय विदेश कार्यालय द्वारा विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए), आरआईएस एवं भारत के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित भारत–जर्मनी 1.5 ट्रैक संवाद, 2020 में भाग लिया और भारत एवं जर्मनी के बीच आर्थिक साझेदारी के बदलते आयामों पर एक प्रस्तुति दी।
- 18 नवंबर 2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भारत–चीन वेबिनार में भाग लिया और 'भारत एवं चीन आर्थिक संबंधः दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ चीन के बढ़ते जुड़ाव' विषय पर व्याख्यान दिया।
- 26 अक्टूबर 2020 को हिंद महासागर अध्ययन सोसायटी (एसआईओएस) द्वारा 'बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों

का सामरिक उपरांत दृष्टिकोण' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया।

- 15 अक्टूबर 2020 को ब्लू इकोनॉमी पर संस्थागत सहयोग के बारे में समुद्री अनुसंधान केंद्र (एमआरसी), पुणे के साथ आयोजित संवादात्मक सत्र में भाग लिया।
- 12 अक्टूबर 2020 को ब्लू इकोनॉमी फोरम द्वारा हिंद महासागर अध्ययन केंद्र, मॉरीशस विश्वविद्यालय के सहयोग से 'हिंद महासागर क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के लिए अवसर एवं चुनौतियां' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया और ब्लू इकोनॉमी पर एक प्रस्तुति दी।

श्री राजीव खेर

प्रतिष्ठित फेलो

- 9 एवं 16 अक्टूबर 2020, 9 और 29 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की अनुशासनात्मक समिति (बेंच II) की बैठक में भाग लिया।
- 16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'बीबीआईएन देशों में लॉजिस्टिक्स कार्य–प्रदर्शन में व्यापक बदलाव लाने' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 9 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा ''आरसीईपी में भारत को क्यों 'शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए' – फायदा और नुकसान'' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 9 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान द्वारा 'कॉरपोरेट गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय लाभ स्थानांतरणः भारत से साक्ष्य' विषय पर आयोजित निदेशक संगोष्ठी पावर टॉक सीरीज 3 में भाग लिया।
- 8 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्व ारा आयोजित 'आईपीआरएस 2.0 के लिए गठित संचालन समिति की दूसरी बैठक' में भाग लिया।
- 3 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित आईपी विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।
- 3 दिसंबर 2020 को आयोजित ट्रू नॉर्थः वार्षिक एलपी सम्मेलन 2020 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 30 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में जी20: रियाद शिखर सम्मेलन, 2020 पर आयोजित आईसीआरआईईआर संगोष्ठी सीरीज में भाग लिया।
- 25 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 'भारत में कृषि–पोषण में जुड़ाव नहीं: नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से एक नजर' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 19 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में कलिंग इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा 'अमेरिकी चुनावों की व्याख्या करनाः भारत, क्षेत्र और विश्व के लिए निहितार्थ' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 18 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की हामीदारी में डब्ल्यूटीओ की व्यापक भूमिका' विषय पर आयोजित पास्कल लैमी के साथ प्रदीप मेहता के वार्तालाप में भाग लिया।
- 17 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (नई दिल्ली) द्वारा दक्षिण केंद्र (जिनेवा), थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क (जिनेवा), नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, केप टाउन विश्वविद्यालय (दक्षिण अफ्रीका), व्यापार व औद्योगिक नीति रणनीतियां (टिप्स), दक्षिण अफ्रीका, और व्यापार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (कंबोडिया) के साथ साझेदारी में 'विकास व समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करना' विषय पर आयोजित वेबिनारों की एक श्रृंखला में भाग लिया।
- 6 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में गुडइयर इंडिया लिमिटेड की बोर्ड और समिति की बैठकों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 2 नवंबर 2020 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित ऑडिट कमेटी, स्वतंत्र निदेशकों की बैठक, ग्राहक सेवा समिति, आईटी रणनीति समिति और निदेशक मंडल की बैठकों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 30 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में चीन पर आयोजित सीआईआई के कोर ग्रुप की बैठक में भाग लिया।
- 28 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में सीआरबी द्वारा 'बेहतर ढंग से आर्थिक बहाली के लिए अनुकूल माहौल बनाना– सरकार से गवर्नेंस तक' विषय पर आयोजित प्रथम उच्च स्तरीय पैनल की बैठक में एक संचालक के रूप में भाग लिया।
- 23 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित हिंद– प्रशांत विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।
- 20 अक्टूबर 2020 को डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क, जिनेवा; नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, केप टाउन विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका; व्यापार व औद्योगिक नीति रणनीतियां (टिप्स), दक्षिण अफ्रीका; और व्यापार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कंबोडिया के सहयोग से

'प्रौद्योगिकी में बढ़त के पीछे सरकार की अदृश्य शक्तिः डब्ल्यूटीओ क्या कर सकता है?' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

- 16 अक्टूबर 2020 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल की बैठकों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।

प्रो. टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 19 अक्टूबर, 2020 को केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी में 'वर्तमान परिदृश्य में कृषि में आईपीआर–प्रासंगिकता' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 अक्टूबर, 2020 को सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, हैदराबाद द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में 'विकास के लिए बौद्धिक संपदा की बदलती गतिशीलता' विषय पर मुख्य भाषण दिया।

डॉ. बी. बालाकृष्णन

विज्ञान कूटनीति फेलो

- 21 दिसंबर 2020 को कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस द्वारा 'भारत में जैव हिफाजत और जैव सुरक्षा' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 21 नवंबर 2020 को वैश्विक युवा अकादमी के दक्षिण एशिया विज्ञान कूटनीति कार्यदल द्वारा आयोजित कार्यशाला में 'विज्ञान कूटनीति– एक परिचय' विषय पर एक मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया।

डॉ. पी.के. आनंद

विजिटिंग फेलो

- 31 अक्टूबर–1 नवंबर 2020 को थिंक टैंक20 (टी20) शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में और 30 नवंबर 2020 को आयोजित 'इटली को सुपुर्द करने के कार्यक्रम' में भाग लिया।
- 4 नवंबर 2020 को 'प्रारंभिक बचपन में देखभाल और निरंतरता' के मुद्दे पर अलग से आयोजित टी20 कार्यक्रम में एक वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 22 अक्टूबर 2020 को टी20 सऊदी अरब द्वारा आयोजित सभी ग्यारह कार्यदलों की बैठकों में भाग लिया, जिसमें कार्यदल 10 की बैठक भी शामिल है और इस दौरान 'सतत और सुदृढ़ ऊर्जा, जल एवं खाद्य प्रणालियों के लिए एकीकृत संबंधित नीतियों' पर हमारे सह–लेखन वाले नीतिगत सार–पत्र को भी कवर किया गया।
- 1 अक्टूबर 2020 को प्रोफेसर मैथियस, प्रारंभिक बचपन शिक्षा की डेसमंड चेयर, डबलिन सिटी विश्वविद्यालय के साथ बाल देखभाल और शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर वेबेक्स परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

श्री के. कृष्णा कुमार

विजिटिंग फेलो

- 31 अक्टूबर–1 नवंबर 2020 को थिंक टैंक20 (टी20) शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में और 30 नवंबर 2020 को आयोजित 'इटली को सुपुर्द करने के कार्यक्रम' में भाग लिया।
- 22 अक्टूबर 2020 को टी20 सऊदी अरब द्वारा आयोजित सभी ग्यारह कार्यदलों की बैठकों में भाग लिया, जिसमें कार्यदल 10 की बैठक भी शामिल है और इस दौरान 'सतत और सुदृढ़ ऊर्जा, जल एवं खाद्य प्रणालियों के लिए एकीकृत संबंधित नीतियों' पर हमारे सह–लेखन वाले नीतिगत सार–पत्र को भी कवर किया गया।
- 1 अक्टूबर 2020 को प्रोफेसर मैथियस, प्रारंभिक बचपन शिक्षा की डेसमंड चेयर, डबलिन सिटी विश्वविद्यालय के साथ बाल देखभाल और शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर वेबेक्स परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 26 अक्टूबर 2020 को विधि संकाय (एफडीयूएसपी) और अंतर्राष्ट्रीय एवं तुलनात्मक कानून विभाग (डीआईएन) द्वारा आयोजित साओ पाओलो विश्वविद्यालय (यूएसपी) के चतुर्थ ब्रिक्स सम्मेलन में 'ब्रिक्स देशों पर कोविड–19 का आर्थिक प्रभाव' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. प्रियदर्शी दाश

सहायक प्रोफेसर

- 31 अक्टूबर, 2020 को सोका विश्वविद्यालय, जापान स्थित दक्षिण एशिया अनुसंधान केंद्र द्वारा 'अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जापान–दक्षिण एशिया संबंध' विषय पर आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'फिनटेक और वैश्विक व्यापार का बदलता परिदृश्य' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 28 अक्टूबर, 2020 को वाणी–एफआईडीसी–हेनरिक बॉल स्टिफटंग द्वारा 'जी20 में भारत के नीतिगत निर्देश के लिए रणनीति तैयार करना' विषय पर आयोजित वेबिनार में अपने विचार व्यक्त किए।
- 13 अक्टूबर, 2020 को ब्रिक्स अकादमिक फोरम में 'विकास के लिए बेहतरीन और सुदृढ़ बुनियादी ढांचा – भारत का हालिया अनुभव' विषय पर प्रस्तुति दी।

प्रकाशन कार्यक्रम

रिपोर्ट

इब्सा में बढ़ता सहयोगः प्रमुख क्षेत्रों से परिप्रेक्ष्य, आरआईएस, नई दिल्ली, 2020

टीसीएम के राष्ट्रीय और वैश्विक संवर्धन के लिए चीन की नीतिगत पहल, आरआईएस, नई दिल्ली, 2020

आरआईएस के परिचर्चा पत्र

#259 **भारत में बल्क ड्रग उद्योगः चुनौतियां और संभावनाएं** द्वारा टी.सी.जेम्स

#258 **भारत से निर्यात की रणनीति तैयार करना** द्वारा दम्मू रवि

आरआईएस के नीतिगत सार–पत्र

#101 **कोविड काल के बाद के सुधारों से भारत में गैस, बिजली और कोयला बाजारों में मूल्य रिकवरी मजबूत हो गई है** द्वारा सुभोमय भट्टाचार्जी

#100 **जी20 शेरपा और वित्त ट्रैकः समानताएं एवं अवसर** द्वारा प्रियदर्शी दाश, सोनल गर्ग व सभ्या राय

#99 **एसडीजी के लिए एसटीआईः जी20 साझेदारी और राष्ट्रीय अनिवार्यताए** द्वारा सचिन चतुर्वेदी, सब्यसाची साहा

विकास सहयोग समीक्षा

- खंडः 3 संख्याः 2ः अक्टूबर, 2020

जी20 डाइजेस्ट

- खंडः 2 संख्याः 2, जनवरी, 2021
- खंड 2, विशेष अंक, पीपी 1–21, अक्टूबर, 2020

एफआईडीसी का परिचर्चा पत्र

- #3ः भारत–अफ्रीका विकास साझेदारी की गतिशीलता

आईओआरए प्रकाशन

- ब्लू इकोनॉमी इनसाइट, नवंबर, 2020

एआईसी प्रकाशन

- आसियान–भारत विकास और सहयोग रिपोर्ट 2021

आरआईएस संकाय का बाहय प्रकाशनों में योगदान

आनंद, पी.के., कृष्णा कुमार और अन्य (2020). 'सतत और सुदृढ़ ऊर्जा, जल एवं खाद्य प्रणालियों के लिए एकीकृत संबंधित नीतियां', कार्यदल10 के तहत टी20 नीतिगत सार–पत्र सतत ऊर्जा, जल और भोजन, सऊदी अरब।

चतुर्वेदी, सचिन; प्रकाश, अनिता और दाश, प्रियदर्शी (सं.). 2020. *एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोर – हिंद–प्रशांत क्षेत्र में विकास और सहयोग।* स्प्रिंगरः सिंगापुर।

चतुर्वेदी, सचिन; प्रकाश, अनिता और दाश, प्रियदर्शी। 2020. 'परिचय' चतुर्वेदी, सचिन; प्रकाश, अनिता और दाश, प्रियदर्शी (सं.) में। *एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोर – हिंद–प्रशांत क्षेत्र में विकास और सहयोग*। स्प्रिंगरः सिंगापुर।

चतुर्वेदी, सचिन और दाश प्रियदर्शी. 2020. 'एएजीसी और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि' चतुर्वेदी, सचिन ; प्रकाश, अनिता और दाश, प्रियदर्शी (सं.) में। *एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोर – हिंद–प्रशांत क्षेत्र में विकास और सहयोग।* स्प्रिंगरः सिंगापुर।

चतुर्वेदी, सचिन 2020. 'कर्ज में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखकर विदेशी फंड का प्रभावकारी ढंग से उपयोग करें', *द डेली स्टार,* 28 अक्टूबर, 2020.

चतुर्वेदी, सचिन 2020. 'होल्डिंग कंपनियां प्रमोटरों को बैंकों से अलग कर देंगी – नियामकीय संरचना को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं', *द टाइम्स ऑफ इंडिया,* 30 नवंबर 2020.

चतुर्वेदी, सचिन, 2020. 'क्या जो बाइडेन व्यापार में ट्रम्पवाद को हराने में सक्षम होंगे?', *द इकोनॉमिक टाइम्स,* 21 दिसंबर 2020.

चतुर्वेदी, एस., ए. अलहर्बी और सब्यसाची साहा 2020. 'जी20 नेतृत्व और एसडीजी रोडमैप के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एवं नवाचार पर वैश्विक पायलट कार्यक्रम की प्रासंगिकता', टी20 सऊदी अरब नीतिगत सार–पत्र, अक्टूबर 2020.

दाश, प्रियदर्शी। 2020. एशिया–प्रशांत में विकास की गति तेज हुईः बेहतरीन अवसंरचना और डिजिटल अर्थव्यवस्था, *जापान स्पॉटलाइट,* नवंबर–दिसंबर 2020.

खेर, राजीव 2020. 'क्या भारत की पीएलआई योजना गलत दिशा में है?' ब्लूमबर्ग, नवंबर 2020.

मोहंती, एस.के. 2020. 'वैश्विक मंदी के दौरान बिम्सटेक की क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलताः क्षेत्रीय सम्मेलन में चीन फैक्टर' पर शोध पत्र पुडुचेरी विश्वविद्यालय।

मोहंती, एस.के. 2020. 'टका बिल्कुल सटीक स्तर पर हैः निर्यात, मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और वृहद आर्थिक स्थिरता से वर्ष 2004 से ही बांग्लादेश में विकास को मिल रही है नई गति'। *आउटलुक इंडिया पत्रिका,* 28 दिसंबर।

श्रीनिवास, के.आर. 2020. *'जैव/जीवन विज्ञान में उभरती प्रौद्योगिकियों/अनुप्रयोगों का संचालनः जीनोम एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी'* चौरासिया, अनुराग, हॉक्सवर्थ सीबीई, डेविड एल., पेसोआ डी मिरांडा, मनोइला (सं.) में, *जीएमओः जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के लिए निहितार्थ,* स्प्रिंगर 2020 पीपी 441–462.

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाषः 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ई–मेलः dgoffice@ris.org.in
वेबसाइटः http://www.ris.org.in

Follow us on:
www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi